CNews सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-345
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सफलता की राह में ठोकरें खाना ज़रूरी है, क्योंकि गिरकर उठने की ताकत ही असली कामयाबी है।

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, रविवार 23 मार्च 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एक्सीडेंट क्लेम में फर्जीवाड़ा करने वालों पर गिरेगी गाज

फर्जीवाड़ा की जांच के लिए डीजीपी को दिए एसआईटी गठित करने के निर्देश

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पुलिस महानिर्देशक को यह निर्देश दिया है। एसआईटी इन धोखाधड़ी की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़े न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह मामला श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की एक अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आया। अपील में छिंदवाड़ा के राकेश वल्तिया को दिए गए मुआवजे को चुनौती दी गई थी।

हर दिन बढ़ रहे ऐसे मामले

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इससे न्यायिक प्रणाली पर गलत असर पड़ रहा है। इसलिए, कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। यह एसआईटी इन मामलों की गहराई से जांच करेगी।

जांच के लिए दिए खास निर्देश

एकलपीठ ने एसआईटी को जांच के लिए कुछ खास निर्देश दिए हैं। एसआईटी को यह देखना होगा कि क्या दावेदार, पुलिस अधिकारी और डॉक्टर आपस में मिले हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी वकील भी दावेदारों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। ऐसे वकील मोटर दुर्घटना दावा मामलों या आपराधिक कानून के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं।

कंपनी ने दी थी चुनौती

मामला राकेश वल्तिया से जुड़ा था। वल्तिया को दुर्घटना में चोट लगने के बाद मुआवजा दिया गया था। कंपनी का कहना था कि वल्तिया ने मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। कंपनी ने आरोप लगाया कि वल्तिया ने जिला अस्पताल (विक्टोरिया) का फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वल्तिया ने खुद माना कि वह कभी भी विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। उसने यह भी कहा कि वह कभी किसी जांच के लिए वहां नहीं गया। कोर्ट ने पाया कि विक्टोरिया अस्पताल के डॉ. शरद द्विवेदी और सुविधा अस्पताल के डॉ. बालकृष्ण डांग ने फर्जी प्रमाण पत्र और इलाज के दस्तावेज तैयार किए थे। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव और एमसीआई को इन डॉक्टरों के खिलाफ जांच करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर को भी दिए जांच के आदेश

वल्तिया ने बताया कि वकील मनोज शिवहरे ने उसे विकलांग प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाए थे। इसके अलावा, दवाइयों के बिल में जीएसटी भी नहीं लगाया गया था। हाईकोर्ट ने एमपी स्टेट बार काउंसिल को मनोज शिवहरे के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिला कलेक्टर को मां फार्मेसी की जांच करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट यह जानना चाहता है कि फार्मेसी को बिना जीएसटी के दवा बेचने का अधिकार किसने दिया। अपीलकर्ता कंपनी की तरफ से अधिवक्ता राकेश जैन ने पैरवी की।

टीबी के खिलाफ भारत की जंग जारी, यूपी में 1,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हुईं टीबी मुक्त

नई दिल्ली। ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) की बीमारी के खिलाफ भारत की जंग जारी है, इसी का नतीजा है कि उत्तरप्रदेश की 1300 से ज्यादा ग्राम पंचायतें टीबी से मुक्त हो चुकी हैं। हालांकि टीबी भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। भारत का इसी साल यानी 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य था। वैसे तो टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिसके अच्छे परिणाम भी देखे जा रहे हैं हालांकि निर्धारित लक्ष्य अब भी काफी दूर बना हुआ है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान टीबी से संबंधित एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हम लगातार टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश में टीबी की घटनाओं की दर में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में प्रति एक लाख लोगों पर 237 लोगों में टीबी का पता चलता था जो 2023 में घटकर 195 रह गया है। नए मामलों में 17.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जो वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में आ रही कमी से दोगुनी से भी अधिक है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है।

टीबी के मामले और मृत्युदर में भी आई कमी

स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2015 की तुलना में 2023 में टीबी के कारण होने वाली मौतों में भी 21 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। सरकार के निरंतर प्रयासों के चलते देश में टीबी उपचार कवरेज भी 32 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बीमारी तो है पर उनका निदान नहीं किया गया, ऐसे लोगों का पता लगाने और उपचार प्रदान करने की दिशा में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। टीबी को देश से खत्म करने के लिए सभी लोगों को साथ आने का भी आह्वान किया गया है। पिछले साल 7 दिसंबर को देशभर में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य टीबी का पता लगाने, उपचार और जागरूकता में तेजी लाना है। मेघालय एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के स्टेट-कोऑर्डिनेटर मेबैंकमेन खारकोंगोर के अनुसार, टीबी उन्मूलन की दिशा में स्पेक्टम करियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां हम रोजाना लगभग 510 सैंपल एकत्र करते हैं और इसकी जांच करके बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर करीब 17 हजार ग्राम पंचायतों ने बीते एक साल में एक भी नया मामला नहीं मिलने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश से साल 2024 में 7,755 ग्राम पंचायतों ने टीबी मुक्त होने का प्रमाण हासिल करने का दावा किया है। इनमें अकेले सिद्धार्थनगर जिले से 216 ग्राम पंचायतों ने राज्य सरकार को आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश के राज्य टीबी अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि 2023 में कुल 1,372 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर हाल ही में तमिलनाडु टीबी प्रसार सर्वेक्षण में 39त्न सबक्लिनिकल टीबी के मामले पाए गए। सब क्लिनिकल टीबी का मतलब उन रोगियों से है जिनमें बीमारी के लक्षण जैसे खांसी या कफ आदि नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को बिना लक्षण वाले मरीजों को निगरानी में लेने और जांच कराने की सलाह दी गई है।

दुनियाभर में टीबी की चुनौती

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एक रिपोर्ट में बताया कि साल 2023 में दुनियाभर में 8 मिलियन (80 लाख) से अधिक लोगों में तपेदिक का पता चला है। यह संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 1995 में ट्रैक रखना शुरू करने के बाद से दर्ज किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले 2022 में डब्ल्यूएचओ ने टीबी के 7.5 मिलियन (75 लाख) मामले दर्ज किए। पिछले साल लगभग 1.25 मिलियन (12.5 लाख) लोगों की टीबी से मृत्यु भी हुई है।

60 हजार सैलरी फिर भी पत्नी मांग रही थी पति से गुजारा भत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा- कोई जरूरत नहीं

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के एक महिला की याचिका खारिज कर दी है। महिला ने कोर्ट के माध्यम से अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग की था। कोर्ट ने कहा कि दोनों एक ही पद पर काम करते हैं और महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, इसलिए पति गुजारा भत्ता नहीं देगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने महिला को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहली याचिकाकर्ता और प्रतिवादी (पति और पत्नी) दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारी अधिकारिता का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनता है। विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया जाता है।

आर्थिक रूप से स्वतंत्र है महिला

बता दें कि महिला ने सुप्रीम कोर्ट में तब अपील की जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और एक ट्रायल कोर्ट ने उसकी गुजारा भत्ते की याचिका को खारिज कर दिया था। महिला के पति की ओर से वकील शशांक सिंह ने उसकी याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह लगभग 60,000 रुपए प्रति माह कमाती है और उसका पद भी पति के समान ही है। पति ने तर्क दिया कि पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है।

सैलरी स्लिप जमा करने के बाद सुनाया फैसला

हालांकि, महिला ने तर्क दिया कि उसकी कमाई की क्षमता को उसके पति को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करना चाहिए। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति की आय लगभग ?1 लाख प्रति माह है। उनकी सैलरी को लेकर विवाद को देखते हुए कोर्ट ने पहले दोनों पक्षों को पिछले एक साल की सैलरी स्लिप जमा करने का निर्देश दिया था। दोनों पति-पत्नी को समान भूमिकाओं में कार्यरत पाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों को बरकरार रखा और याचिका को खारिज कर दिया।

करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल पर कसा शिकंजा, मां-बेटे पर एफआईआर

भोपाल। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा केस में अब पांचवीं जांच एजेंसी की एंट्री हो गई है। लोकायुक्त, ईडी, आयकर विभाग और डीआरआई के बाद अब ग्वालियर पुलिस ने सौरभ शर्मा और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सौरभ और उमा शर्मा के खिलाफ ग्वालियर के सिरोल थाना में शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे परिवहन विभाग की तरफ से धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है।

साल 2016 में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति लेते समय सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा ने शपथ पत्र में बड़े भाई सचिन शर्मा की छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की बात छिपाई थी। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद अब ग्वालियर में दोनों पर मामला दर्ज कराया गया है। सौरभ की नियुक्ति को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू पहले ही लोकायुक्त में शिकायत कर चुके थे।

एक जनवरी 2025 को संयुक्त परिवहन आयुक्त की ओर से एक पत्र मिला था। जिसमें सेवानिवृत परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर दिए गए शपथ पत्र की जांच के निर्देश थे। सहायक परिवहन आयुक्त ने जांच की और सर्विस रिकॉर्ड मंगाया। सौरभ शर्मा ने शपथ पत्र में यह जिक्र नहीं किया कि उसका बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में है। सौरभ की नियुक्ति के लिए उसकी मां उमा शर्मा ने भी शपथ पत्र दिया था। जिसमें बड़े बेटे की सरकारी नौकरी की बात छिपाई थी।जांच के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग में संपर्क किया गया और वेबसाइट से कर्मचारियों की सूची निकाली तो वहां सौरभ के बड़े भाई सचिन शर्मा के सड़क विकास निगम रायपुर में तैनात होने की पुष्टि हुई। जिससे शपथ पत्र झूठे होने का प्रमाण मिला है।

जांच एजेंसियां इन पाइंट्सा पर जांच में जुटी

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी मनी ट्रेल और प्रॉपर्टी के दस्तावेज, तो इनकम टैक्स विभाग सौरभ के दोस्त चेतन सिंह गौर की गाड़ी से मिले 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। लोकायुक्त आय से ज्यादा संपत्ति की जांच तो डीआरआई इस बात की जांच कर रही है कि जो सोना मिला है, वो लीगल तरीके से लिया गया है या नहीं? काली कमाई को कॉलोनी बनाने में खपाए जाने का कनेक्शन भी जांच एजेंसियों को मिला है। अब ग्वालियर पुलिस ने सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

एंजल वन और आइकॉनिक एसेट की रिपोर्ट में बड़ा दावा

खपत के मामले में भारत बनेगा ग्लोबल लीडर

नई दिल्ली। भारत में खपत लगातार बढ़ रही है। देश की कुल जीडीपी में 56 फीसदी का योगदान देने वाला यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी वृद्धि की रफ्तार सबसे तेज है। इसके दम पर भारत जल्द ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दुनिया की खपत राजधानी बन जाएगा। एंजल वन और आइकॉनिक एसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता आधार की वजह से भारत में खपत 2034 तक बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। इसमें एकल परिवार के चलन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी वजह से भारत में घरेलू विकास जनसंख्या वृद्धि से आगे निकल रहा है और यह बढ़ती खपत का प्रमुख चालक बनकर उभर रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में टैक्स के मोर्चे पर करदाताओं को दी राहत से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे 3.3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धिशील खपत को बढ़ावा मिलेगा। इसमें भारतीय जीडीपी को एक फीसदी तक बढ़ाने की क्षमता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में अगले 25 वर्षों में पिछले 25 साल की तुलना में 10 गुना अधिक बचत होने की उम्मीद है। 1996-97 से 2022-23 के बीच भारत की कुल बचत 12 लाख करोड़ डॉलर थी, जो 2027 तक करीब 10 गुना बढ़कर 103 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। इससे वृद्धिशील उपभोग की व्यापक संभावनाएं खुलेंगी। खास बात है कि सरकार की नीतियों से भारत वैश्विक कार्यबल वृद्धि में भी अग्रणी बनने के लिए तैयार है।

उपभोग के मोर्चे पर अमेरिका-चीन की राह पर चलने को देश तैयार

एंजल वन एवं आइकॉनिक एसेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा, आर्थिक और आय विस्तार के दौरान अमेरिका व चीन दोनों देशों में गैर-विवेकाधीन खर्च की तुलना में विवेकाधीन उपभोग अधिक रहा। भारत भी अब इसी राह पर चलने के लिए तैयार है। प्रति व्यक्ति आय में मजबूत वृद्धि के दौर में अमेरिका में उपभोग खर्च में 10 गुना की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ भारत में भी उपभोग खर्च में ऐसी ही बढ़ोतरी देखे जाने की उम्मीद है।?

रिपोर्ट की अन्य खास बातें...

-विवेकाधीन उपभोग में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, आभूषण और एसेसरीज तेजी से उभरने वाले सेगमेंट हैं।

-92 फीसदी खुदरा व्यापार अब भी किराना स्टोर के जरिये होता है।

-आधुनिक खुदरा व्यापार के लिए भी आगे बढ़ने और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का एक बड़ा अवसर है।

-भारत में अमेरिका की कुल आबादी से अधिक जनरेशन जेड की संख्या हैं। 2035 तक खर्च किया जाने वाला हर दूसरा रुपया जनरेशन जेड की जेब से आएगा, जिससे खपत वृद्धि को जोरदार समर्थन मिलेगा।

वैश्विक खपत में होगा 16 फीसदी हिस्सा

दुनिया की कुल खपत में भारत की हिस्सेदारी 2050 तक बढ़कर 16 फीसदी पहुंच सकती है, जो 2023 में 9 फीसदी थी। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सिर्फ उत्तरी अमेरिका ही भारत से आगे होगा।

सुमित्रा महाजन जी मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई एक राष्ट्र एक एक चुनाव विषय पर परिचर्चा

संवादाता । विजय मिश्रा । सिटी चीफ इंदौर। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर एक परिचर्चा का आयोजन इंदौर के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्व विद्यालय के सभागार में किया गया।

आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन एवं म.प्र. उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री रोहित आर्य विषय के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए।महापौर श्री पुष्य मित्र भार्गव एवं जीव जंतु कल्याण बोर्ड,भारत सरकार के सदस्य श्री राम रघुवंशी भी विशेष अतिथि के रूप में आयोजन में शामिल हुए।

भाजपा वृद्धश प्रकोष्ठ म. प्र. के सह संयोजक श्री लोकेंद्र वर्मा इस आयोजन के संयोजक एवं डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय,इंदौर मुख्य सहयोगी संस्थान की भूमिका में रहे।

कार्यक्रम का आरंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण,दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्र गान वंदे मातरम के साथ हुआ। संस्थान की कुलगुरु डॉ. दीपिका पाठक ,रजिस्टार श्री संदीप गुप्ता एवं संस्थान के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत तुलसी के पौधे प्रदान करके किया।

संस्थान की कुलगुरु डॉ दीपिका पाठक ने स्वागत भाषण में संस्थान में पधारे अतिथियों का शाब्दिक अभिनंदन करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव विषय के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का वैचारिक समर्थन किया।

भाजपा वृद्धश प्रकोष्ठ के संभागीय पदाधिकारी श्री अक्षय पहुरकर सहित विजय बिंजवा एवं श्री मति संगीता तंबोली प्रकोष्ठ की अपनी अपनी जिला टोली के सहित आयोजन में उपस्थित रहे।भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नगर पदाधिकारी पंकज चौहान,म. प्र. वृद्धश महासंघ के शशिकांत सातपुते कई वृद्धश संचालकों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए।मंच संचालन संस्थान की श्रीमती अभिलाषा तिवारी ने किया।

कार्यक्रम के अंत में संस्थान की कुलगुरु एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए।आयोजन में मुख्य सहयोगी संस्थान होने के लिए मुख्य अतिथि श्री मति सुमित्रा महाजन सहित अन्य सभी अतिथियों ने सम्मिलित रूप से संस्थान की कुलगुरु डॉ दीपिका पाठक का अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

मुख्य वक्ता श्री रोहित आर्य ने अपने वक्तव्य में एक राष्ट्र एक चुनाव से होने वाले लाभों को बिंदुवार श्रोताओं के समक्ष रखा।

कार्यक्रम के संयोजक श्री लोकेंद्र वर्मा ने आभार माना।

अतिथियों द्वारा संस्थान में वृक्षा रोपण कर एक राष्ट्र एक चुनाव का संदेश देने वाली तख्तियों को गैस के गुब्बारों के द्वारा आसमान में छोड़ा गया।

पीड़ित वाहन मालिकों ने चंदन नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत

नशेड़ियों का तांडव, रातभर तोड़े वाहन, दहशत में शहर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। रात के अंधेरे में नशे में धुत सिरफिरे उपद्रवियों ने शहर में आतंक मचा दिया। राज नगर, कालानी नगर और टेकचंद धर्मशाला के पास खड़े कई वाहनों को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। इन सिरफिरों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को निशाना बनाया और पत्थर-डंडों से उनकी तोड़फोड़ की। घटना का पता सुबह चला, जब स्थानीय रहवासी सोकर उठे और अपने घरों के बाहर आकर देखा। इसके बाद सभी पीड़ित वाहन मालिक शिकायत दर्ज कराने चंदन नगर थाने पहुंचे।

13 वाहन मालिकों ने दर्ज करवाई शिकायत

चंदन नगर थाना क्षेत्र में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। अब तक करीब 13 वाहन मालिकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये

सभी वाहन मालिक राज नगर से लेकर कालानी नगर के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, उपद्रवियों का एक समूह दोपहिया वाहनों पर सवार होकर आया और नशे की हालत में उन्होंने खड़े वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। किसी भी वाहन को देखकर वे गुस्से में पत्थर और डंडे लेकर टूट पड़ते थे।

उपद्रवियों का कहर, सीसीटीवी में कैद होने की संभावना

रहवासियों का कहना है कि यह घटना संभवत: आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई होगी। इस उम्मीद में पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात कही है। चश्मदीदों के अनुसार, ये सिरफिरे नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने एक के बाद एक कई वाहनों को निशाना बनाया और उन्हें बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस तोड़फोड़ से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली बार ये सिरफिरे किसे निशाना बनाएंगे।

शहर में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब शहर में इस तरह की घटना घटी हो। इससे पहले भी कई इलाकों में इस तरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि, प्रशासन की ओर से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन अपराधियों के हौसले कम होते नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि ऐसे सिरफिरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जाएं।

बजट चर्चा पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद

ईमानदार नेता है नीतीश कुमार लेकिन लालू फुसलाकर ले गए थे

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में बजट चर्चा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भारत खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों में था, लेकिन आज शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने बजट पर चर्चा का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा देश को बदलने की चाहत होनी चाहिए। वो मोदी सरकार में है। कांग्रेस की सरकार के समय जल, थल, वायु, पाताल, नभ में घोटाले किए। देश तब पांच खराब अर्थव्यवस्था वाले देशों में था, लेकिन आज भारत श्रेष्ठ पांच अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के अवसर दे रहे हैं। भारत में 70 मोबाइल फैक्ट्री हैं। उसमें सात लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। कम उम्र के युवा स्टार्टअप से लाखों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में खिलौना उद्योग, फुटवियर उद्योग बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। मोदी सरकार ने जनता के जीवन को आसान बनाया है। ये बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भाजपा का रिश्ता पुराना है। वे ईमानदार नेता हैं।

बीच में लालू प्रसाद यादव फुसलाकर ले गए थे, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से कई बार बोल चुके हैं कि वे मोदी जी के साथ हैं। हम भी चुनाव में उनके साथ रहेंगे। इस दौरान कार्यक्रम को भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मेयर पुष्य मित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सचिन बंसल ने किया, आभार धीरज खंडेलवाल ने माना। इस दौरान कार्यक्रम को भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, मेयर पुष्य मित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का आभार धीरज खंडेलवाल ने किया।

लाडली बहना योजना से क्रय शक्ति बढ़ी

मध्य प्रदेश के बजट पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के बजट पर डबल इंजन की सरकार का प्रभाव दिख रहा है। खर्च ज्यादा होने के बावजूद प्रदेश की जीडीपी ज्यादा है। सरकार का विजन बड़ा है। मध्य प्रदेश में निवेश भी अच्छा आ रहा है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना से कुछ लोग सहमत भी हैं और असमहत भी, लेकिन इस योजना के कारण क्रय शक्ति बढ़ी है। इंदौर के हर वार्ड में 50 से 60 लाख रुपये आ रहे हैं।

राहुल गांधी होमवर्क ठीक से नहीं करते

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों और वंचितों के लिए अवसर नहीं होते। मेरा सवाल है कि वे खुद किस मेरिट के आधार पर कांग्रेस में पद पाते हैं। राहुल गांधी ठीक से होमवर्क नहीं करते। उनका ट्यूटर बदलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपना वजूद खत्म कर रही है। पास्को एक्ट को लेकर कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के प्रति जजों को संवेदनशील होना चाहिए।

इंदौर में मौसम का बदलता मिजाज तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस था, जो शुक्रवार को घटकर 33.6 डिग्री सेल्सियस रह गया। यह तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहा, जो कुछ हद तक राहत देने वाला था। हालांकि, रात के तापमान में एक खास बदलाव देखने को मिला।

दूसरी ओर, इंदौर में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। गुरुवार को यह 17.8 डिग्री था, जबकि शुक्रवार को यह बढ़कर 21.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस वृद्धि के कारण रात के समय अधिक गर्मी महसूस की गई। गर्मी का असर रात में भी दिखाई देने लगा, जो स्थानीय निवासियों

के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

मौसम प्रणाली का प्रभाव और भविष्य का पूर्वानुमान

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्र ने बताया कि वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव 23 मार्च तक बना रहेगा। इसके बाद 24 मार्च से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर दिखाई देगा। इससे तापमान में बदलाव हो सकता है और साथ ही मौसम की स्थिति में भी बदलाव हो सकता है।

मार्च के आखिरी सप्ताह में बढ़ेगा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मार्च के आखिरी सप्ताह में दिन और रात दोनों के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है।

इससे गर्मी का असर और अधिक बढ़ेगा। सामान्यतः 20 मार्च के बाद तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ष उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिससे तापमान में अस्थायी गिरावट देखी गई। हालांकि, 25 मार्च के बाद अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, और मार्च के अंत तक यह 36-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अप्रैल में भी तापमान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है।

एमवाय हॉस्पिटल को मिली हाईटेक मशीन न्यूरो और हड्डी सर्जरी अब होगी आसान

इंदौर। एमवाय हॉस्पिटल में न्यूरो और हड्डी रोग से संबंधित ऑपरेशन अब और भी आसान हो जाएगा। अस्पताल को दो नई एडवांस एक्स-रे इमेजिंग मशीनें मिल गई हैं, जिससे ऑपरेशन थिएटर में सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इन हाईटेक एक्स-रे मशीनों की कई खूबियां हैं, लेकिन दो विशेषताएं इसे और खास बनाती हैं। यह मशीनें मरीजों के इलाज के साथ-साथ डॉक्टरों और सर्जनों के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होंगी।

मोबाइल यूनिट से लैस हाईटेक एक्स-रे मशीन

नई एक्स-रे मशीन मोबाइल यूनिट से लैस है, जिसका वजन करीब 400 किलोग्राम है। हालांकि, इसमें लगे पहियों की मदद से इसे ऑपरेशन थिएटर सहित अस्पताल के किसी भी हिस्से में आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा, इस मशीन के एक्स-रे कैमरे को 180 डिग्री के एंगल तक मूव किया जा सकता है, जिससे डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग दिशाओं से स्पष्ट इमेज प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन का डिज़ाइन अंग्रेजी अक्षर ष्ट के आकार का होने के कारण इसे सी-आर्म मशीन कहा जाता है।

बेंगलुरु की कंपनी से खरीदी गई उन्नत मशीनें

मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीष गोयल ने बताया कि ये मशीनें बेंगलुरु की प्रसिद्ध आलेन्जर्स कंपनी से खरीदी गई हैं। सामान्यत: एक मशीन की कीमत लगभग 10 लाख रुपये होती है। इस हिसाब से दोनों मशीनों की कुल लागत 20 लाख रुपये आई, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में इंस्टॉलेशन की फीस जोड़कर कुल खर्च लगभग 25 लाख रुपये हुआ है। इन उन्नत मशीनों को अस्पताल में शामिल करने से इलाज में आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा।

सर्जरी में मिलेगी बड़ी सुविधा, मरीजों को होगा लाभ

इस हाईटेक मशीन में दो स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें से एक स्क्रीन पर ऑपरेशन के दौरान मरीज का ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाई देगी, जबकि दूसरी स्क्रीन पर सर्जरी का लाइव प्रसारण होगा। इससे सर्जन डॉक्टरों को ऑपरेशन करने में काफी आसानी होगी और ऑपरेशन की सटीकता बढ़ेगी। इन मशीनों की खूबियों के कारण ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए इसे किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा है। इसके उपयोग से अधिक मरीजों के ऑपरेशन किए जा सकेंगे, जिससे अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता और बेहतर होगी।

बाल विवाह रोकने पहुंची टीम, नाबालिग ने दी आत्महत्या की धमकी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। सांवेर के बूढ़ी बरलई गांव में एक नाबालिग के विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह उड़नदस्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां पूरा परिवार इस विवाह को रोकने के विरोध में खड़ा हो गया। पिता द्वारा किए गए खर्च और विवाह की तैयारियों को देखते हुए नाबालिग स्वयं आगे आई और विवाह न होने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगी। रोते हुए उसने कहा कि अगर आज उसकी शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी।

प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, सगाई पर अड़ा परिवार

बाल विवाह उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक, पुलिस निरीक्षक सुमन तिवारी, सीमा तिवारी, कोर ग्रुप सदस्य शैलेष शर्मा, मोनिका बघाय, सुकन्या पाटीदार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित बड़ी टीम वहां पहुंची।

लेकिन जब परिवार नहीं माना तो तहसीलदार पूनम तोमर को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने परिवार को समझाया कि बाल विवाह कराने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपए का दंड हो सकता है। अंततः प्रशासन की समझाइश के बाद विवाह को रोका गया, लेकिन परिवार सगाई कराने पर अड़ा रहा।

पिता द्वारा जबरन विवाह, बालिका ने की शिकायत

इसके विपरीत, पालदा में रहने वाली एक नाबालिग का विवाह उसके पिता द्वारा जबरन एक सप्ताह पहले करवा दिया गया था। लड़की इस विवाह से खुश नहीं थी और उसने इसका विरोध करने का साहस दिखाया। विवाह की जबरदस्ती के खिलाफ उसने पुलिस थाना भंवरकुआं में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय उसे वहां से भगा दिया और उसकी फरियाद नहीं सुनी।

कलेक्टर की हस्तक्षेप से हुई जांच के निर्देश

पुलिस की अनदेखी के बावजूद बालिका ने हार नहीं मानी और कलेक्टर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इस मामले में प्रशासन की तत्परता के बाद ही नाबालिग को न्याय मिलने की उम्मीद जगी। यह घटना बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत को दर्शाती है।

अध्यक्ष विभा पटेल बोलीं-सुरक्षा देने में सरकार फेल

एमपी में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला अपराधों को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में हंगामे के बाद महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी है। शनिवार को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने कहा महिलाओं पर अपराध और अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। सिलसिलेवार रूप से अभियान और आंदोलन चलाए जाएंगे। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन होगा। इसी कड़ी में बेटी बचाओ पखवाड़ा की भी शुरुआत कांग्रेस करेगी।

प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल बताया कि प्रदेश के सतना जिले में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, सहित प्रदेश भर में महिलाओं, युवतियों, नाबालिगों के साथ प्रदेश में लगातार हो रही की घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आज महिला कांग्रेस नेत्रियों द्वारा महिलाओं-बच्चियों की सुरक्षा में नाकाम प्रदेश की नाकारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर महिला उत्पीड़न को लेकर विरोध दर्ज किया गया।

प्रदेश नें रोज बलात्कार की 20 घटनाएं

विभा पटेल ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, युवतियों और अबोध-मासूम बच्चियों के साथ शोषण, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश में दिल दहलाने वाली रोज बलात्कार की लगभग 20 अमानवीय घटनाएं सामने आ रही है, जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के चलते आपराधिक सोच के व्यक्तियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ और निड़र होकर घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूक रहे है।

घटनाओं से महिलाओं, बच्चियों में भय

पटेल ने कहा कि सतना में घटित हुई घटना से साबित होता है कि प्रशासन बहन-बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं।

बढ़ते महिला अपराधों से सभ्य समाज कलंकित हो रहा है। इन घटनाओं से महिलाओं, बच्चियों में भय और आमजन में आक्रोश व्याप्त है। पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जो स्वयं गृहमंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं, उनसे न तो मुखिया की कुर्सी संभल रही है और न ही गृहमंत्री का दायित्व ठीक से संभाल पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गृहमंत्री का दायित्व किसी अच्छे, योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंप दें, ताकि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चौक-चौबंद किया जा सके, अपराधियों पर लगाम लगे, ताकि प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों को सुरक्षा और सम्मान मिल सके, आमजन को आपराधिक प्रवृत्ति के असामाजिक तत्वों से राहत मिल सके।

जल गंगा जल संवर्धन अभियान से पानी की एक-एक बूंद बचाएगी राय सरकार

30 मार्च से शुरू होगा 90 दिवसीय अभियान

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार अब पानी की एक-एक बूंद बचाएगी। इसके लिए आने वाले दिनों में स्कूलों से लेकर सड़कों तक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। दरअसल, राय सरकार 30 मार्च से जल गंगा, जल संवर्धन अभियान शुरू करने जा रही है। इस 90 दिवसीय अभियान की शुरुआत वर्ष प्रतिपदा के दिन उजैन की शिप्रा नदी से की जाएगी। इसका समापन 30 जून को होगा। इस मुहिम की थीम जन सहभागिता से जल स्त्रोतों का संवर्धन एवं संरक्षण रखी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने कहा कि जल से ही हमारा कल सुरक्षित है। यह प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जिसका संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए, हम सब मिलकर जल संसाधनों की सुरक्षा का संकल्प लें और एक समृद्ध भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से जल बचाने के लिए जागरूक रहने और जल संरक्षण के सभी उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राय सरकार भी इस साल 30 मार्च से जल गंगा जल संवर्धन अभियान प्रारंभ करने जा रही है। जल संरक्षण में जन सहभागिता बढ़ाने और अधिकाधिक जल संरचनाओं के निर्माण की मंशा से जुड़ा यह अभियान लगातार 90 दिन तल चलेगा। उन्होंने इस अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। उनका कहना है कि है कि पानी से ही जिंदगानी है। हम सभी को जल की बूंद-बूंद बचाने की जरूरत है। जल से ही हम सबका आने वाला कल सुरक्षित है।

गांवों से लेकर शहरों तक चलेगा जागरूकता अभियान

गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत जल संचय की कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पौधरोपण-जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन किया जाएगा। गांव-गांव में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम होंगे। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में बचों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। गर्मी के मौसम मंच सरकारी स्कूलों में जल संरक्षण की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बचों के लिए पीने के पानी की टंकी की साफ-सफाई कराई जाएगी।

पीएम मोदी का जल संरक्षण अभियान बना जन आंदोलन

इस अभियान के मद्देनजर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि राय सरकार गांव-गांव में लोगों को पेयजल और किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को भी कोई परेशानी न हो इसके लिए वन क्षेत्र-प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं को पुनर्विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जल संरक्षण अभियान देशभर में एक व्यापक जन-आंदोलन बन चुका है। मध्यप्रदेश सरकार भी खेत का पानी खेत में-गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर जल संरक्षण की दिशा में अभियान चला रही है।

इतने बड़े स्तर पर होंगे काम

बता दें जल गंगा जल संवर्धन अभियान में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक-धार्मिक महत्व वाले तालाबों, जल स्त्रोतों, देवालयों में काम किए जाएंगे। मंदिरों के पास मौजूद जल स्त्रोतों की सफाई में संतों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय समुदाय, प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। विक्रम संवत् के पहले दिन वरुण पूजन और जलाभिषेक के साथ अभियान की विधिवत शुरुआत की जाएगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने अमृत सरोवर अभियान में एक हजार नये तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन विकास कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपये का खर्च हो सकता है। तालाब निर्माण के लिए अब तक 300 स्थानों का चयन किया जा चुका है। जियोग्रॉफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) पद्धति से शेष स्थानों की चयन प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। साथ ही 100 करोड़ रुपये की लागत से 50 हजार नए खेत-तालाब बनाए जाएंगे। ताकि, लघु एवं सीमांत किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिले। विभाग का लक्ष्य वर्ष-2025 में एक लाख नए खेत-तालाब बनाने का है।

जन-जन को जोड़कर नदियों का संरक्षण

अभियान के तहत में प्रदेश की 50 से अधिक नदियों के वॉटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण-संवर्धन पर जोर दिया जाएगा। बेतवा सहित अन्य नदियों की जल धाराएं न टूटें, इसके लिए जनसमुदाय की सहभागिता से गेबियन संरचना, ट्रेंच, पौधरोपण, चेकडैम और तालाब निर्माण जैसे काम किए जाएंगे। इस काम में आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप से नर्मदा परिक्रमा पथ को भी चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद मनरेगा के जरिये जल संरक्षण और पौधरोपण की कार्य योजना तैयार की जाएगी।

सरकार तैयार करेगी इतने लाख जलदूत

जल गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत पहले से बनी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेशभर के तालाबों के गहरीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल आयोजित की जाएंगी। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देकर स्थानीय लोगों को जल संरचनाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत हर गांव से 2 से 3 महिला-पुरुष का चयन कर राय में एक लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे। साथ ही सीवेज का गंदा पानी जल स्त्रोतों में मिलने से रोकने के लिए सोक पिट निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के दौरान सदानीरा फिल्म समारोह, जल सम्मेलन, प्रदेश की जल परंपराओं पर आख्यान, चित्र प्रदर्शनी समेत कई आयोजन होंगे। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है।

एमपी बोर्ड पांचवीं और आठवीं की कॉपी जांचने का काम 80% पूरा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। प्रदेश के पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। प्रदेश भर के सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 25 लाख विद्यार्थी परिणाम के इंतजार में है। यह परिणाम 30 मार्च को आना था, लेकिन अब तक 80 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूरा हुआ है। मूल्यांकन कार्य 24 मार्च तक समाप्त करना था। अब तीन दिन शेष है। ऐसे में मूल्यांकन कार्य पूरा होना संभव नहीं है। वहीं शिक्षक मूल्यांकन केंद्र नहीं पहुंच रहे हैं। इस कारण उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने का काम नहीं पूरा हो पा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जो समय-सारिणी तय किया था। उसके हिसाब से मार्च के अंत तक पांचवीं व आठवीं का परिणाम आना था, लेकिन अब तक 20 फीसद उत्तरपुस्तिकाओं को जांचना बाकी है। निजी स्कूलों के अंग्रेजी माध्यम के चार लाख विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस कारण निजी स्कूलों के शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है। राजधानी के चार मूल्यांकन केंद्रों पर 834 शिक्षकों को साढेय तीन लाख उत्तरपुस्तिकाओं को जांचने के लिए लगाया गया है। इसमें पांचवीं की एक लाख 26 हजार और आठवीं की दो लाख पांच हजार उत्तरपुस्तिकाएं हैं। जिनके मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

भोपाल के एमपी नगर में पकड़ाया 15 किलो गांजा, 4 तस्कर गिरफ्तार

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। क्राइम ब्रांच टीम ने उड़ीसा से भोपाल गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 15 किलो 160 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एमपी नगर जोन-1 स्थित यश बैंक के सामने 4 लोग थैलों में गांजा रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पाकर क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी अशोक मरावी और उनकी टीम मौके पर पहुंची। यहां घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एमपी नगर जोन-1 में स्थित यश बैंक के सामने एक पेड़ के पास 4 संदिग्ध लोग बैठे हैं। ये चारों लोग अपने पास थैले लिए हुए हैं, जिनमें गांजा भरा हुआ है। वे किसी ग्राहक को बेचने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी अशोक मरावी ने तुरंत अपनी टीम को सक्रिय किया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसमें उप निरीक्षक इरशाद अंसारी, अजीज खान, सहायक उप निरीक्षक चंद्रमोहन मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक रामकुमार गौतम, प्रधान आरक्षक विश्वजीत भार्गव, मजज्फर अली, आरक्षक बृजमोहन ब्यास, मुकेश शर्मा, शादाब, महावीर, ऋषिकेश त्यागी, विवेक नामदेव और संध्या शर्मा को शामिल किया गया।

भ्रष्टाचार के आरोप में फरार टीआई को मिली अग्रिम जमानत

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। भोपाल में फर्जी कॉल सेंटर संचालकों को बचाने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में अंडर ग्राउंड हुए टीआई जितेंद्र गढ़वाल को जबलुपर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। हाईकोर्ट जज मनिंदर एस भट्टी की कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। इधर केस के मुख्य आरोपी एएसआई पवन रघुवंशी अब भी फरार है। उसके साथ एएसआई मनोज सिंह और प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य आरोपी मोइन अंशुल पार्षद भी फरार हैं। बता दें कि पवन पर रिश्वत के 4.94 लाख रुपए घर में रखने के आरोप हैं। वह लाइन हाजिर होने के बाद भी अहम केसों की डायरियां अपने साथ ले गया था।

उसका आचरण लगातार संदिग्ध था। कार्यवाहक निरीक्षक जितेंद्र गढ़वाल ने डीसीपी जोन-1 को गोपनीय पत्र के माध्यम से उसके संदिग्ध आचरण की जानकारी दी थी। इस आधार पर 28 फरवरी को उसे लाइन हाजिर किया गया। इसकी रिपोर्ट रोजनामचा में भी दर्ज की गई थी। उनके वकील की ओर से यह तमाम तर्क कोर्ट में दिए। जिसके आधार पर उन्हें जमानत का लाभ मिला। टीआई ने पवन को लाइन हाजिर किए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से उसे अपने पास मौजूद तमाम केस डायरियों का चार्ज दूसरे को ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए, लेकिन वह डायरियां अपने साथ लेकर चला गया। इन डायरियों में फर्जी कॉल सेंटर केस की डायरी भी मौजूद थी। इस बात की रिपोर्ट भी रोजनामचा में दर्ज है।

बोले-मेरे कार्यकाल में बना कानून, बीजेपी का विरोधी रवैया सर्वविदित

ओबीसी आरक्षण पर कमलनाथ ने सरकार को घेरा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर लगी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून मार्च 2019 में बनाया गया था, जिसे हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लागू होने से रोकने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का ओबीसी विरोधी रवैया सर्वविदित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सामाजिक साइट पर लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा कानून के तहत भर्तियां करने को स्वतंत्र है। इससे स्पष्ट है कि आज की स्थिति तक 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के कानून पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पिछले पांच साल से हुई भर्तियों में ओबीसी को 27त्न आरक्षण दे सकती थी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अब सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को

लागू कराने के लिए पैरवी करे।

नेता प्रतिपक्ष बोले-सरकार प्रतिबद्धता दिखाए

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसको लेकर एक्स पर किए गए संदेश में कहा है कि अब ओबीसी को 27त्न आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्धता दिखाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में ही सरकारी भर्तियों में ओबीसी को 27त्न आरक्षण देने का कानून बनाया गया था। जिसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार मौजूदा कानून के तहत विज्ञापन जारी कर भर्तियां करने को स्वतंत्र है। इसका सीधा मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पिछले 5 सालों से हुई भर्तियों में ओबीसी को 27त्न आरक्षण दे सकती थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के चलते ऐसा होने नहीं दिया। अब मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आने के बाद मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है कि ओबीसी आरक्षण को लागू कराने के लिए पैरवी करे।

सम्पादकीय

किसानों का आंदोलन खत्म, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी अब भी अनिश्चित

अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सेना के नियंत्रण वाले 'रेस्ट हाउस' में शिफ्ट कर दिया गया। नाराज डल्लेवाल ने पानी तक पीने से इंकार कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई अचानक की गई, लेकिन हम इसे पूर्व-नियोजित मानते हैं। यह पंजाब की मान सरकार की रणनीति भी है।

किसानों का 404 दिन पुराना आंदोलन मात्र चार घंटे में ही कुचल दिया गया। पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सीमेंट बैरिकेड तोड़ दिए गए, अस्थायी ढांचे, मंच और तंबू उखाड़ दिए गए। अनाज, सब्जियां आदि सडक़ पर बिखेर दी गईं। गुरुवार को 700 से अधिक आंदोलित किसानों को हिरासत में लिया गया था। अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को सेना के नियंत्रण वाले 'रेस्ट हाउस' में शिफ्ट कर दिया गया। नाराज डल्लेवाल ने पानी तक पीने से इंकार कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई अचानक की गई, लेकिन हम इसे पूर्व-नियोजित मानते हैं। यह पंजाब की मान सरकार की रणनीति भी है। प्रमुख किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7वें दौर की बातचीत कर रहे थे। जब वे लौटे, तो सब कुछ बिखर चुका था। पंजाब में ऐसी पुलिसिया कार्रवाई चौंकाती है, विरोधाभास की व्याख्या भी करती है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने आंदोलनकारियों को भोजन, पानी, शौचालय की सुविधाएं मुहैया कराई थीं। तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किसानों को जेल में डालने के केंद्र सरकार के आग्रह तक को खारिज कर दिया था। पंजाब में भी 'आप' की सरकार है और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दिलाने का वायदा किया था। अब 'आप' के सामने लुधियाना उपचुनाव की चुनौती है, लिहाजा व्यापारियों और उद्योगपतियों के गंभीर दबाव में किसानों को खदेडऩे का फैसला लेना पड़ा। पंजाब में फरवरी, 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। साफ है कि आंदोलित किसानों का तबका तो 'आप' के खिलाफ जनमत देगा। वैसे आंदोलन के मद्देनजर किसान संगठन बिखर कर खंड-खंड हो चुके हैं, लिहाजा सभी वार्ताएं बेनतीजा साबित हो रही हैं। चंडीगढ़ की 7वीं बैठक के दौरान किसानों ने एक दस्तावेज-सा पेश किया था, जिसके मुताबिक एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 25-30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन किया गया था। बताते हैं कि उस अपुष्ट दस्तावेज पर केंद्रीय वाणिज्य-उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नाराजगी जताई। किसानों को यह भी दो टूक कहा गया कि यदि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई, तो पंजाब से गेहूं और धान की खरीद का कोटा अन्य राज्यों के साथ बांटना पड़ेगा। पंजाब से जो सर्वाधिक सरकारी खरीद की जाती है, वह कोटा भी कम हो जाएगा। बताया जाता है कि इस पर किसान चौंक कर खामोश हो गए। चूंकि एमएसपी पर बेनतीजा बैठकों के ही दौर चल रहे हैं, लिहाजा अब हमारा भी अंदेशा यह है कि मोदी सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं देगी। कृषि विशेषज्ञ भी इसे संभव और व्यावहारिक नहीं मानते। आंदोलन बिखरने और एमएसपी का संवाद भी, अंततः, टूटने के बाद यह सवाल मौजू है कि अब किसान क्या करेंगे? अब शंभू के साथ-साथ जींद (हरियाणा) से सटे खनौरी बॉर्डर को भी किसान-मुक्त करा लिया गया है। औद्योगिक संगठनों के आकलन थे कि किसान आंदोलन के कारण इन 404 दिनों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हर रोज के करीब 72 लाख रुपए टोल टैक्स का भी नुकसान झेलना पड़ा है। चूंकि सीधा असर पंजाब की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, लिहाजा करीब 70 लाख लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। बहरहाल, एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा 'जुमला' साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर देशभर के किसान एकमत-एकजुट नहीं हैं।

भारत में बढ़ता प्रदूषण: सरकारों की उदासीनता और गंभीर खतरे

अनुमानित जनसंख्या का संकेत है कि 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और चीन का स्थान दूसरा होगा। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत, परंतु विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भारत में होगी। देश का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। भारत को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस-दीर्घकालिक उपाय चाहिए

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं करती। उनका कहना था कि प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं, तो हम नीचे से अपनी जमीन को खिसका रहे हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2024 की रिपोर्ट उनके पर्यावरण को लेकर दिए गए बयान को सही साबित करती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 20 प्रदूषित शहरों में दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के कई शहर भी शामिल हैं। भारत के 13 शहरों की हालत सर्वाधिक खराब है। जिस मेघालय के बारे में हरी-भरी वादियों और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के सुरम्य स्थलों की कल्पना की जाती थी, उसका बर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहर है। बर्नीहाट में प्रदूषण का उच्च स्तर स्थानीय कारखानों, जैसे शराब निर्माण, लोहा और इस्पात संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण है। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान के चार शहर और चीन का एक शहर भी इस सूची में हैं। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यूएयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी की इस रिपोर्ट में भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है, जो 2023 में तीसरे स्थान पर था। देश के 35 प्रतिशत शहरों में पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना अधिक है। दिल्ली में स्थिति और भी गंभीर है, जहां वार्षिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता 2023 में 102.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढक़र 2024 में 108.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2024 में पीएम 2.5 (2.5 माइक्रोन से छोटे प्रदूषण कण) की सांद्रता में 7 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2023 में 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटकर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई।

दिल्ली में वायु प्रदूषण साल भर एक गंभीर समस्या बना रहता है, जो सर्दियों में और भी खतरनाक हो जाता है। प्रतिकूल मौसम, वाहनों से निकलने वाला धुआं, धान की पराली जलाना, पटाखों का धुआं और अन्य स्थानीय स्रोत हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। पीएम 2.5 कण फेफड़ों और रक्तवाहिकाओं में प्रवेश कर सांस की बीमारियों, हृदय रोग और कैंसर का कारण बन सकते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं और पराली जलाने जैसे स्रोतों पर सख्त नियंत्रण के बिना स्थिति में सुधार मुश्किल है। शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत से बर्नीहाट (मेघालय), दिल्ली, मुल्लांपुर (पंजाब), फरीदाबाद, गुरुग्राम (हरियाणा), लोनी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ (राजस्थान) शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत के लिए एक चेतावनी है कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। वायु प्रदूषण भारत में एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। लांसेट प्लैनेटरी हेल्थ के रिसर्च के अनुसार वर्ष 2009 से 2019 तक हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत पीएम 2.5 प्रदूषण के लंबे संपर्क के कारण हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रदूषण के कारण भारतीयों की औसत आयु 5.2 साल कम हो रही है। भारत में बढ़ते प्रदूषण से देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदूषण से हर साल 95 अरब डॉलर यानी देश की जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। वर्ष 2019 में डलबर्ग नाम की ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म ने बताया था कि भारत में प्रदूषण के कारण 95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसका कारण काम की उत्पादकता में कमी, छुट्टियां लेना और समय से पहले मौत है।

यह रकम भारत के बजट का लगभग 3 फीसदी और देश के सालाना स्वास्थ्य खर्च का दोगुना है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में भारत में 3.8 अरब कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, जिससे 44 अरब डॉलर की चपत लगी। वर्ष 2070 तक भारत के नेट-जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए हरेक क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन कम करने की जरूरत है। इस दिशा में बीते वर्षों में सरकारों ने ईवी वाहनों पर सबसिडी देने की शुरुआत की है, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम-कुसुम योजना के भी लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि सकारात्मक कदम है। भारत अपने अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है और धीरे-धीरे कोयला आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रहा है। इन सभी संयुक्त प्रयासों से आने वाले भविष्य में वायु प्रदूषण पर असर पड़ेगा। इसके बावजूद सरकारी प्रयास आधे-अधूरे हैं। वर्ष 2023 की एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदूषण का माइक्रो-लेवल असर भारत की अर्थव्यवस्था को मैक्रो-लेवल पर प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर पिछले 25 सालों में भारत ने प्रदूषण को आधा भी कम किया होता, तो 2023 के अंत तक भारत की जीडीपी 4.5 फीसदी ज्यादा होती। लांसेट हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़े असर ने देश की जीडीपी को 1.36 फीसदी धीमा कर दिया। अगर प्रदूषण पर कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और खराब हो सकती है। वर्ष 2023 की डलबर्ग रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक, जब भारत की औसत उम्र 32 साल होगी, वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। भारत में पर्यावरण की कई समस्याएं हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरा और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण भारत के लिए चुनौतियां हैं।

पर्यावरण की समस्या की परिस्थिति 1947 से 1995 तक बहुत ही खराब थी। 1995 से 2010 के बीच विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अध्ययन के अनुसार, अपने पर्यावरण के मुद्दों को संबोधित करने और अपने पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने में भारत दुनिया में सबसे तेजी से प्रगति कर रहा है। फिर भी, भारत विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के स्तर तक आने में इसी तरह के पर्यावरण की गुणवत्ता तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर है। पर्यावरण की समस्या का, बीमारी, स्वास्थ्य के मुद्दों और भारत के लिए लंबे समय तक आजीविका पर प्रभाव का मुख्य कारण हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास और शहरीकरण व औद्योगीकरण में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार तथा तीव्रीकरण, तथा जंगलों का नष्ट होना इत्यादि भारत में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण हैं।

अनुमानित जनसंख्या का संकेत है कि 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और चीन का स्थान दूसरा होगा। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत, परंतु विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत भारत में होगी। देश का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। भारत को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस और दीर्घकालिक उपायों की जरूरत है। प्रश्न यह भी है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों को यह तय करना है कि उदाहरण दूसरे देशों के ज्यादा प्रदूषित होने का गिनाया जाए या अपने देश की हालत को सुधारा जाए। यह निश्चित है कि जब तक देश के राजनीतिक दल पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनाने पर सहमत नहीं होंगे, तब तक हर साल यह समस्या जन-धन को भारी नुकसान पहुंचाती रहेगी। प्रदूषण से निपटने के लिए समूह समाज को एकजुट करने की जरूरत है।

विधायकों का सत्ता मोह: क्या जनता के सेवक ऐसे ही व्यवहार करेंगे?

सत्ता का नशा शायद सिर चढ़कर बोलता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले असम के एक वीडियो ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी है। यह मामला धुबड़ी जिले के पूर्व बिलासीपाड़ा के आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक शमसुल हुदा से संबंधित है।

कहा जाता है कि कुर्सी यानी सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है। देश के विभिन्न राज्यों में कई सांसद और विधायक अपनी करनी से समय-समय पर इस बात का चरितार्थ करते रहे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर हिंदी पट्टी के राज्यों के अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से भी सामने आती रही हैं। ताजा मामले में असम के एक विधायक ने एक मामूली बात पर एक व्यक्ति को सरेआम पीट दिया। धुबड़ी जिले के विधायक शमसुल हुदा का पारा इस बात से चढ़ गया था कि शिलान्यास समारोह में उनको जो फीता काटना था उसका रंग लाल की बजाय गुलाबी क्यों था।

असम में यह कोई पहली घटना नहीं है। इस साल फरवरी में इत्र कारोबारी और पूर्व सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तो निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई की पत्नी के खिलाफ ही अभद्र टिप्पणी कर दी थी। हालांकि, बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली। बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान बराक घाटी के करीमगंज में स्थानीय वोटरों ने विधायक विजय मालाकार पर धमकाने का आरोप लगाया था। तब विधायक महोदय ने कहा था कि या तो बीजेपी को वोट दें या फिर बुलडोजर के लिए तैयार रहें।

मैं जानता हूं कि आपका घर कहां है। उस समय इस पर काफी विवाद हुआ था। कांग्रेस ने पुलिस और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसी तरह करीब तीन साल पहले कछार जिले में बीजेपी विधायक कौशिक राय पर ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। तब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तक से की गई थी। उस शिकायती पत्र पर 16 सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, लेकिन राय भी साफ बच निकले।

पश्चिम बंगाल भी ऐसे मामलों से अछूता नहीं है। बीते साल अक्तूबर में सीपीएम ने एक महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न के आरोपी अपने पूर्व विधायक तन्मय भट्टाचार्य को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने एक महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में जेल मंत्री अखिल गिरि को माफी मांगने और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, लेकिन आखिर जनप्रतिनिधियों को इतना गुस्सा क्यों आता है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसकी जड़ें खुद को सबसे ताकतवर समझने वाली मानसिकता में छिपी हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि खुद को तमाम कायदे कानूनों और सरकारी अधिकारियों से ऊपर मानते हैं। भले ही वो किसी अदनी सी नगरपालिका का पार्षद ही क्यों न हों।

कोलकाता में राजनीतिक विश्लेषक दीपंकर कर कहते हैं कि तमाम लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं। दरअसल, किसी को धमकी देकर या दो-चार थप्पड़ लगा कर वो साफ बच निकलते हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई से हिचकती है। कई मामलों में तो पिटने और अपमानित होने वाले लोग भी उनके खिलाफ शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन लोगों को पता होता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता।

विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में फिर भी गनीमत है। दूसरे राज्यों में तो कुछ जनप्रतिनिधियों पर अपराधियों को संरक्षण देने से लेकर बलात्कार और हत्या तक के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है।

करीब चार दशक तक बंगाल में पत्रकारिता कर चुके तापस मुखर्जी ने तमाम राजनीतिक दलों और उनकी सरकार को कवर किया है। मुखर्जी कहते हैं कि खासकर कम उम्र में या पहली बार विधायक या सांसद बनने वाले लोगों में ऐसी प्रवृत्ति आम है।

ऐसे लोग कुर्सी की ताकत नहीं पचा पाते। उनका कहना है कि ऐसे ज्यादातर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उनका मनोबल बढ़ता रहता है। कानून तो सबके लिए समान है। जब तक ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ठोस तंत्र विकसित नहीं होता, असम जैसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी।

दूसरा पहलू: 1857 की क्रांति से शुरू हुआ सफर

आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की बदलती तस्वीर

अठारहवीं सदी के विशाल दरवाजे से प्रवेश करते समय लातिन अमेरिकी कथाकार ग्रैबियल गार्शिया मारखेज की मनोरोगियों की पृष्ठभूमि पर लिखी बेचैन करने वाली कहानी, मुझे तो बस एक कॉल करनी थी, जहन में तैरने लगती है।

सामने 172 एकड़ में औपनिवेशिक काल की इमारतों वाला हरा-भरा कैंपस है। आगरा के प्रख्यात मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डॉ. दिनेश राठौड़ कहते हैं, 150 साल से ज्यादा पुराने इस संस्थान ने नए तौर-तरीकों को तेजी से अपनाया है।

फिल्मों में मानसिक रोगियों के इलाज को जिस तरह से दिखाया जाता है, वैसा कुछ अब नहीं है। यह आम अस्पताल की तरह है। ओपीडी में रोजाना लगभग 250 मरीज आते हैं। स्थायी मरीजों?में ज्यादातर कुछ?हफ्तों?में ठीक होकर चले जाते हैं। जिनका परिवार नहीं है, वे यहां रहते हैं और फिर पुनर्वास संगठनों की मदद से बेहतर जीवन गुजारते हैं। इलेक्ट्रिक चेयर पर बिजली के झटके जैसा कोई इलाज यहां नहीं है।

तो फिर उस अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल कॉल्विन की क्या कहानी है, जो 1857 की क्रांति में पागल हो गया था और उसकी कब्र आगरा फोर्ट में दीवान-ए-आम के सामने है। इसके लिए हमें गुजरे दौर में लौटना होगा।

आगरा में 1859 में पागलखाना बनाने की तात्कालिक वजह नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध, जिसका मुख्यालय आगरा था, के लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन का क्रांति के दौरान की परिस्थितियों की वजह से पागल होना था। उन्हें यहां कभी भर्ती नहीं किया गया। उनकी मौत की तात्कालिक वजह 9 सितंबर, 1857 को हैजे से हुई बताई गई। बाद में ब्रिटिश सरकार को लगा कि क्रांति से प्रभावित अंग्रेजों के इलाज के लिए आगरा में मानसिक संस्थान बनना चाहिए। इस संस्थान में भर्ती होने वाली पहली मरीज एक भिखारिन थी। उस समय आईजी जेल ही इसके प्रमुख होते थे।

1904 में लखनऊ का पागलखाना बंद कर इसके मरीजों और रिकॉर्ड को आगरा शिफ्ट कर दिया गया, ताकि एक ही जगह बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी साल आईजी जेल की जगह डॉ. काकरन को पहला मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाया गया। 1957 में संस्थान के प्रमुख डॉ. केसी दुबे की पहल ने पूरी दुनिया का ध्यान आगरा की ओर खींचा। यह था मानसिक मरीजों के वार्ड खुले रखना। 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वायत्तशासी निकाय बना दिया और मेंटल हॉस्पिटल की जगह नया नाम दिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हॉस्पिटल। ...और आज यहां खिली धूप में अपनों और समाज से ठुकराए लोग भविष्य का ताना-बाना बुनते हैं।

सहारनपुर में भाजपा नेता ने अपनी पत्नी व तीन बच्चों को लाइसेंसी पिस्टल से मारी गोली

तीनों बच्चों की हुई मौत, पत्नि की हालत नाजुक, हायर सेंटर रेफर

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । (गंगोह), सहारनपुर जिले के थाना गंगोह क्षेत्र में नानौता-गंगोह मार्ग पर गांव सांगाठेडा में आज दोपहर भाजपा नेता 40 वर्षीय योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी व तीन बच्चों को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। जिसमें 10 वर्षीय बालिका श्रद्धा समेत तीनों बच्चों की मौत हो गयी। जबकि योगेश रोहिला की पत्नी नेहा को नाजुक हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय देवांश और उसकी बहन श्रद्धा की मौत मौके पर ही हो गयी थी जबकि छह वर्षीय शिवांश ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि आज दोपहर पति- पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इसी दौरान योगेश रोहिला पुत्र स्वर्गीय रमेश रोहिला ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी और तीनों बच्चों को उनके सिर से सटाकर गालियां चलायी जिसमें दो बच्चों की मौके पर ही जान चली गयी। पुलिस उसकी पत्नि नेहा और एक पुत्र शिवांश को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां शिवांश की भी मौत हो गयी। घटना को अंजाम देने के बाद योगेश रोहिला घटना स्थल पर ही बना रहा और उसने स्वयं पुलिस को सूचना देकर मौके बुलाया। पुलिस ने जब योगेश रोहिला से घटना के बारे में पूछताछ की तो रोहिला ने कहा कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शक था इसी कारण उसने उन पर गोलियां चलाई है। पुलिस ने आरोपी योगेश रोहिला को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। वारदात में उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में मौजूद अन्य सबूतों की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस वारदात के पीछे असली वजह क्या थी।

जिला क्षय रोग अधिकारी ने प्रतिभागियों को बच्चों में टीबी की तुरंत जाँच एवं उपचार पर जोर दिया

सभी प्रतिभागियों को विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गयी

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स एवं जिला क्षय रोग विभाग के द्वारा होटल के आर प्लाजा में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लाक स्तर से सी डी पी ओ, बी सी पी एम , आर बी एस के टीम के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में होने वाले टी बी रोग की समय पर जाँच एवं निदान रहा। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स राज्य स्तर से मुक्त शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियो को इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. सर्वेश सिंह एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. नन्दलाल शर्मा ने प्रतिभागियों को बच्चों में टीबी की तुरंत जाँच एवं उपचार पर जोर दिया। बच्चों में QR CODE के माध्यम से लक्षणों के आधार पर सम्बंधित ष्ट।ष्ट पर भेजने की बात पर जोर दिया गया। यूनिसेफ़ के जिला समन्वयक अमित शर्मा द्वारा सभी प्रतिभागियों को विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गयी और बताया गया कि विशेष संचार रोग नियंत्रण का कार्यक्रम 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाएगा। जिसमें 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। जिसमें आशा और आंगनबाड़ी घर-घर जाकर संचार रोग नियंत्रण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इनकी रोकथाम के विषय में समाज मे जागरूकता का कार्य करेंगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों यूनिसेफ़, डब्ल्यूएचओ के जिला एवं मंडल स्तरीय अधिकारीयों ने भाग लिया।

लालबर्रा में कबाड़ी दुकानों का अवैध धंधा

चोरी का सामान खुलेआम बिक रहा,प्रशासन मौन

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ
लालबर्रा, शहर में अवैध कबाड़ व्यापार ने जड़ें जमा ली हैं। चोरी का सामान, सरकारी संपत्ति से जुड़ी सामग्री और वाहनों के महंगे पुर्जे कबाड़ी दुकानों में खुलेआम बिक रहे हैं। गली-मोहल्लों से लेकर मुख्य बाजारों तक अवैध कबाड़ का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है,लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह विफल नजर आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि थाना क्षेत्र के आसपास चोरी का सामान आसानी से उपलब्ध है। इन दुकानों पर पुलिसकर्मियों की आवाजाही तो रहती है,लेकिन कार्रवाई का नामोनिशान नहीं है। नागरिकों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध व्यापार बढ़ रहा है,जिससे चोरी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।
अपराध की जड़ बन चुकी हैं कबाड़ी दुकानें कबाड़ी दुकानों में चोरी हुए सामान की बिक्री एक आम बात हो चुकी है।स्थानीय लोगों के अनुसार,बिना किसी दस्तावेज के वाहनों के इंजन,बैटरी,वायरिंग, लोहे के पाइप और सरकारी संपत्ति के सामान यहां बेचे जा रहे हैं। कई दुकानों के पास वैध लाइसेंस तक नहीं हैं,लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि चोरी का माल आसानी से कबाड़ियों के पास पहुंचने के कारण अपराधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। बड़े गिरोह इन दुकानों को चोरी का सामान खपाने का अड्डा बना चुके हैं, जिससे वाहन चोरी और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं।
कैसे पहुंच रहा चोरी का सामान कबाड़ियों तक? स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, चोरी की वारदातों में सक्रिय अपराधी सीधे कबाड़ियों से संपर्क करते हैं और चोरी का सामान यहां खपाया जाता है। इसके बाद यह सामान बड़े व्यापारी या अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। कुछ मामलों में तो बिना किसी दस्तावेज के बाइक और चारपहिया वाहन तक कबाड़ी दुकानों में मिल जाते हैं। कई बार वाहन मालिक जब अपनी गुमशुदा गाड़ियों की तलाश करते हैं, तो उनके कुछ हिस्से इन्हीं कबाड़ी दुकानों में मिलते हैं। यह साबित करता है कि शहर में कबाड़ी दुकानों के जरिये अवैध व्यापार चरम पर है।
प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को इस गोरखधंधे की पूरी जानकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन की इस चुप्पी के पीछे कोई मिलीभगत है? जब इस मामले को लेकर अधिकारियों से सवाल किए गए, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर इसे टालने की कोशिश की। वहीं,कई पुलिसकर्मी यह कहकर बचते नजर आए कि इस संबंध में कोई ठोस शिकायत नहीं मिली है।
सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में उठा मामला, फिर भी निष्क्रिय प्रशासन कबाड़ का यह अवैध कारोबार अब सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया है। कई बार इस मामले को उजागर किया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। नागरिकों का आरोप है कि जब तक प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगा,तब तक यह गोरखधंधा इसी तरह चलता रहेगा।
नागरिकों की मांग...अवैध कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी और कानूनी कार्रवाई हो स्थानीय नागरिकों और समाजसेवियों ने प्रशासन से मांग की है कि कबाड़ी दुकानों की सघन जांच की जाए और जो दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही हैं, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। चोरी का सामान खरीदने और बेचने वाले लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो ताकि इस अवैध व्यापार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर इसी तरह अपराधियों को खुली छूट मिलती रहेगी?

बूदाबहू मंदिर ट्रस्ट कमेटी में जिला न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त

दमयंती नगर तहसीलदार होंगे ट्रस्ट कमेटी के रिसीवर ,ट्रस्ट को किया भंग

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ
दमोह, दमोह जिले के प्रसिद्ध बंदा बहू मंदिर में ट्रस्ट कमेटी द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओ सहित करोड़ों रुपए के घोटाले की गई जांच के उपरांत एस डी एम के प्रतिवेदन के उपरांत जिला न्यायालय द्वारा इस मामले में आदेश करते हुए मंदिर ट्रस्ट कमेटी में रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किये जाने के बाद बूंदाबहू मंदिर संघर्ष समिति ने देर शाम मंदिर में आरती ढ़ोल नगाड़े की धुन पर आरती कर, मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय गोविन्द पुजारी कि फोटो लेकर घंटाघर गये जहां पर जमकर आतिशबाजी की गई। उसके तदोपरांत बूंदाबहू मंदिर संघर्ष समिति की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें नगर पुरोहित पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक व अन्य के द्वारा शिकायत किए जाने पर कलेक्टर ने अनुबिभागीय अधिकारी दमोह को जांच किए जाने के निर्देश दिए थे जिसमें लाखों रुपए की आर्थिक अनिमितताओं को किए जाने की जांच प्रमाणित पाए जाने पर एसडीएम ने जिला न्यायाधीश को इस मामले में बूंदाबहू मंदिर में रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। बूंदाबहू मंदिर संघर्ष समिति के सदस्य पंडित सुनील गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश ने लगातार ही इस मामले में सभी तथ्यों पर दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुनने के उपरांत पाया गया कि तहसीलदार दमोह द्वारा जो जांच की गई थी और उस जांच को अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रतिवेदन सहित जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितता पाई गई थी और इस मामले में तहसीलदार दमयंती नगर को मंदिर की व्यवस्था हेतु रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जिसमें प्रारंभिक रूप से एवं प्रथम दृष्टिया जांच में यह पाया गया कि श्री देव जानकी रमन बूदाबहू मंदिर ट्रस्ट कमेटी दमोह में आर्थिक अनियमिताएं हुई हैं। इस मामले में जांच लगने में समय भी लग सकता है। इस कारण से इस मंदिर में इस प्रकरण के निराकरण होने तक रिसीवर के रूप में दमयंती नगर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति प्रदान जिला न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने एसडीएम दमोह को दी है। इस दौरान पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक, नीलमणि दीक्षित, पप्पू महाराज,कैलाश प्यासी, अजय गर्ग,आशीष कटारे, रामकृपाल शास्त्री, रामेश्वर शर्मा,मोनू पाठक, वैभव अयाची, अनिल मिश्रा,सुनील गौतम, संजय सरवरिया, किशोरी अग्रवाल, मनोज सोनी,संजय यादव, मोंटी रैकवार, विनय असाटी,सचिन असाटी की विशेष रूप से मौजूदगी रही।बूंदाबहू मंदिर संघर्ष समिति की पत्रकार वार्ता का सफ़ल संचालन युवा सकल हिन्दू समाज जिला अध्यक्ष मोंटी रैकवार व आभार जिला सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित अनिल मिश्रा के द्वारा व्यक्त किया गया।

खंड संसाधन केंद्र गुनारसा पर एक दिवसीय विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
देवबंद (सहारनपुर), खंड संसाधन केंद्र गुनारसा पर एक दिवसीय विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। जिसमें प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक /इंचार्ज अध्यापक सहित समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती नीलम तोमर ने कहा कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति के रूप में विद्यालय प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य अध्यापक और अभिभावक के सहयोग प्रत्येक आवश्यकता और समस्या को लांघते हुए विद्यालय का सफल संचालन करना है। जिसमें छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था, विद्यालय की सम्पूर्ण आवश्यकता, आय -व्यय, समस्याओं का निदान शामिल है। इस अवसर पर ए. आर. पी. योगेंद्र मलिक, डॉक्टर संजय उपाध्याय, प्रभात कुमार यादव और शिवकुमार ने जनपहल माडयूल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। बड़ी संख्या मे अध्यापकों ने प्रतिभाग किया।

ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

बैठक में सर्वसम्मति से गुडग़ांव से पत्रकार कुलभूषण शर्मा को प्रदेश महासचिव व राजकुमार वालिया को बनाया प्रदेश मुख्य सलाहकार

अश्विनी वालिया । सिटी चीफ
कुरुक्षेत्र, 22 मार्च ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की प्रदेश स्तरीय एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वालिया की अध्यक्षता में एवं प्रदेश उपाध्यक्ष देसराज भटनागर व राजकुमार वालिया के सानिध्य में प्रदेश कार्यालय कुरुक्षेत्र सेक्टर-17 नजदीक पुराना बस स्टैंड के पास संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम संघ पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। इसके उपरांत सेक्टर-17 स्थित प्रदेश स्तरीय कार्यालय का विधिवत तरीके से शुभारंभ किया गया। नए कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकारिणी का सर्वसममति से विस्तार किया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपप्रधान देसराज भटनागर, मुख्य सलाहकार राजकुमार वालिया, मुख्य संरक्षक दलबीर सिंह मलिक, संरक्षण सुशील शर्मा, जिला महासचिव गुलशन ग्रोवर ने सभी सदस्यों को नए प्रदेश कार्यालय के शुभारंभ पर बधाई व शुभकामनाएं दी और कहा कि नया कार्यालय खुलने से पत्रकार मीटिंग कर अपने समस्या रख सकेंगे, इससे आपसी भाईचारा व तालमेल भी बना रहेगा। बैठक में दो सदस्यों की सर्वसम्मति से रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की गई है। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी वालिया ने बैठक में नए सदस्यों की घोषणा करते हुए बताया कि गुडग़ांव से वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण शर्मा को ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ का प्रदेश महासचिव व वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार वालिया को प्रदेश का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलों की माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे और पत्रकार एकता संघ को प्रदेश के विभिन्न जिलों में नए जिलाध्यक्ष व ब्लॉक स्तर पर भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही और संघ को मजबूत करने के प्रयास बारे में कहा गया। इसके साथ-साथ कहा गया कि प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं को सरकार से अवगत करवाया जाएगा और उन्हें हल करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ के प्रदेश उपप्रधान डीआर भटनागर,मुख्य संरक्षक दलबीर मलिक, मुख्य सलाहकार राजकुमार वालिया, महासचिव कुलभूषण शर्मा, संरक्षक सुशील शर्मा के अलावा ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ कुरुक्षेत्र जिला के महासचिव गुलशन ग्रोवर, उपप्रधान संजीव कुमार, संगठन सचिव अनिल वर्मा, कोषाध्यक्ष राजकुमार कौशिक, शमशेर सिंह व अन्य सदस्य मौजूद रहे।

महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के तत्वाधान में 20 वां संत नरहरि पुण्योत्सव एवं सामाजिक महासम्मेलन कार्यक्रम आज

लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ
लालबर्रा, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज जिला बालाघाट द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में 20 वां संत शिरोमणी श्री नरहरि महाराज पुण्योत्सव एवं महासम्मेलन का आयोजन आज रविवार को भटेरा रोड स्थित स्वर्णकार समाज के संत श्री नरहरि भवन बालाघाट में सभी सामाजिक स्वजातीय बंधुओं के सहयोग से किया जा रहा है।
इस आयोजन के संबंध में महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष श्री अशोक फाये, एवं सचिव श्री एच. कावड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 19 वर्षों से महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज द्वारा यह सामाजिक मिलन कार्यक्रम सामाजिक एकता,सौहाद्र एवं हर्षोल्लास के साथ जिला स्वर्णकार भवन में मनाया जाता है,जिसकी तैयारी विगत दो माह से हमारी सामाजिक कार्यकारिणी द्वारा क्षेत्रांतर्गत स्वजातीय बंधुओं के घरों में जाकर इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का प्रयास किया गया है साथ ही आयोजित कार्यक्रमों के बारे में बताया कि आमंत्रित अतिथियों एवं सामाजिक जनों की उपस्थिति में सामाजिक आराध्य संत श्री नरहरि महाराज प्रतिमा के पूजन अर्चन से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी तथा साथ ही सामाजिक युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन एवं स्वजातीय मेधावी छात्र- छात्राओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को पुरूस्कृत कर सम्मानित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान उद्बोधन एवं वार्तालाप के माध्यम से समाज को एकजुट एवं संगठित करने हेतु संगोष्ठी एवं विचार आपस में साझा किए जाएंगे तत्पश्चात सभी सामाजिक जनों के साथ भोजन कर कार्यक्रम की समाप्ति की जाएगी। जिला स्वर्णकार समाज कार्यकारिणी एवं समस्त तहसील कार्यकारिणी ने उक्त सामाजिक सम्मेलन में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अधिक से अधिक संख्या में स्वजातीय भाई बहनों से उपस्थित होने की अपील की है।

जिला स्तरीय पशु उपचार शिविर, कार्यशाला एवं गौवत्स प्रदर्शनी कार्यक्रम संपन्न

दुग्ध उत्पादन की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें सहयोग किया जायेगा- पशुपालन महाविद्यालय के डीन डॉ. राजेश शर्मा

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ
दमोह, दमोह जिला पहला जिला है जहां पर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया गया और 09 गायों में यह सफल हुआ है, यदि हम इसमें जाएंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, इसमें और गति चाहते हैं तो हमारे पास एक ही विकल्प है पशुपालन का, उदाहरण के रूप में यदि एक घर में पांच गाय तैयार कर दें, उनसे बछिया तैयार करके उनके जीवन में बदलाव आ ही जाएगा और यह हम मिशन मोड पर चला दे, यहां के डॉक्टर को कोई भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, जो मांगेंगे वह किया जायेगा, परंतु लक्ष्य लेकर के कि हमें इस गांव में 10, 20 या इस ब्लॉक में 500 करना है तो पूरे जिले का लक्ष्य दीजिए, समय-समय पर समीक्षा कीजिए और उसके परिणाम एक साल के बाद आएगा यदि आप समीक्षा करेंगे तो लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा। इस आशय के विचार प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल नरसिंहगढ़ में पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह अंतर्गत जिला स्तरीय पशु उपचार शिविर, कार्यशाला एवं गौवत्स प्रदर्शनी के कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, गौरव पटेल, संगीता श्रीधर, नर्मदा सिंह एकता, खरगराम पटैल, कपिल शुक्ला, एसडीएम निकेत चौरसिया, उपसंचालक पशुचिकित्सा डॉ संजय पाण्डे सहित बड़ी संख्या में पशुपालकगण और किसान बंधु मौजूद रहे।

पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटैल ने कहा जिले में कोई बड़ा कैंप लगाए, जिससे यूनिवर्सिटी के लोग भी आए, यहीं ऑपरेशन करें, जो मशीने चाहिए होगी वह उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन यहां कुछ अलग मॉडल खड़ा करके दिखाएं की पशुपालन एक ऐसा मॉडल है, जिससे किसान के जीवन में बदलाव हम ला सकते हैं, उससे उत्साहित होकर दूसरे जिलों तक यह संदेश जाए, बहुत जल्दी हम यहां पर गौशाला बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोशिश करेंगे की पूरी 10 हजार गौवंश रखें लेकिन यदि पूरे 10 हजार गौवंश नहीं भी रख पाए तो 5 से 7 हजार गौवंश रखकर इस साल गौशाला को शुरू किया जायेगा। यह इतनी अच्छी जगह है कि वहां आप सभी लोग पिकनिक मनाने और बच्चों के जन्मदिन मनाने जाएंगे।

राज्यमंत्री लखन पटैल ने कहा हमारे जिले की कुछ हिस्से में ओलावृष्टि हुई है, कल रात को ही कलेक्टर से बात की है, उन्होंने बताया है की सारी जगह पर अधिकारियों को भेज दिया है और सुबह से सर्वे करने के लिए भी अधिकारी निकल गए हैं। कलेक्टर ने खुद सुबह से घूम जायजा लिया हैं। सर्वे किया जा रहा है जिसमें जो भी आंकलन निकलेगा उसके नियम अनुसार किसानों को राहत दी जाएगी।

राज्यमंत्री ने किसानों का स्वागत करते हुये कहा पशुपालक अपनी गाय और बछड़े लेकर आए हैं, स्वागत इसलिए क्योंकि उन्होंने वह काम किया जिसकी हम अभी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का भी स्वागत करता हूं, जो इस मेले में पधारकर कुछ सीख कर, कुछ नया लेकर के जाएंगे, उन सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है। कृषि विद्यालय से आए सभी डॉक्टर, सभी प्रोफेसर, पत्रकार मित्रों सभी का बहुत-बहुत स्वागत वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं।

राज्यमंत्री ने कहा इस मेले को लगाकर एक संदेश देना चाहता हूं सेक्स सॉर्टेड सीमेन और बछिया जो यहां बुलाई गई है, वह इसलिए कि लोग यह देखें और देखकर के उसका अनुसरण करें। आधा लीटर, 1 लीटर दूध देने वाली गाय, एक

जेनरेशन के बाद अच्छी बछिया पैदा कर सकती हैं और अच्छी गाय बन सकती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी-सभी सामने देखा है। कई बार दूसरे जिलों से मांग आती है कि सीमेन नहीं मिल रहा है, आपको दमोह जिले के लिए जितना सेक्स सॉर्टेड सीमेन चाहिए होगा, उतना उपलब्ध कराएंगे यही एक उपाय है। हमारे पास जो निराश्रित गौवंश सड़कों पर घूम रहा है उसका एकमात्र उपाय है, कि हम उनको अच्छी नस्ल में बदल दें और आने वाली जनरेशन अच्छी हो जाए, तो कोई भी गाय को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा इस मेले को लगा करके मेरा उद्देश्य है कि सभी लोगों तक संदेश जाए और नई तकनीक से हम नया काम कर सकेंगे।

राज्यमंत्री ने कहा ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है जैसे यह बछिया तैयार की है उसमें उनका टारगेट देंगे कि हर साल कम से कम 20 प्रतिशत जो वहां पर गौवंश है उसको सेक्स सॉर्टेड सीमेन या एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से अच्छी वैरायटी की बछिया तैयार करें, जिससे आने वाले 2 से 3 साल बाद गौशाला में ही गाय बनाकर के दूध देने का काम करेगी, इन चीजों से गौशाला आत्मनिर्भर बनेगी, किसानों की समस्या हल होगी, गौशाला में बनने वाले खाद और उत्पाद हम तक पहुंच सकेंगे इन गौशालाओं से सभी किसानों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा डॉक्टर सोमिल राय ने प्रयास करके लगभग 22 गायों का एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट में आधे से अधिक गुण नहीं आ सकते हैं लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमेन से 100 प्रतिशत गुण आ जाता है, जिस गाय का भ्रूण बनाया है, उसके 100 प्रतिशत गुण उसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें सफलता 50 प्रतिशत के अंदर रहती है, इस काम में डॉक्टर का सपोर्ट करना चाहिए।

राज्यमंत्री ने कहा नरसिंहगढ़ में कॉलोनी से लगी हुई 500 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग को कलेक्टर ने दे दी है, उसमें गोकुल गौशाला, बड़ी गौशाला जहां 10 हजार से अधिक गाय रखी जायेंगी और जो काम यहां हो रहा है वह भी होगा, उसके साथ-साथ वहां पर सीएनजी भी बनाएंगे, इसके साथ-साथ जैविक खेती के खाद्य की उपलब्धता की जायेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में लगभग 20-22 गौशाला बना रहे हैं, उनमें लगभग 2 लाख से अधिक गौवंश होगा, गौशाला बनाने के पीछे तीन-चार कारण है जिसमें सरकार लगभग 2 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, एक गौशाला का खर्च लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए होगा। गौशाला बनाने में कम से कम 20 करोड़ रुपए और उसके बाद गौशाला में होने वाले जो कार्यक्रम है, जैसे सीएनजी बनाई जायेगी, सीएनजी का प्लांट लगाया जायेगा तो लगभग 20-25 लाख का प्लांट लगेगा, उसमें जो गोबर गैस बनेगी उस गैस का अलग उपयोग होगा, गोबर गैस के गोबर का खाद लगभग 50-60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अब नई तकनीक आ गई है कि 7 से 8 दिन में खाद बनाकर तैयार हो जाएगी, अभी खाद में ढाई प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, एक प्रतिशत फास्फोरस और एक प्रतिशत पोटाश होता है, लेकिन जो खाद 7 से 8 दिन में बनकर तैयार होगी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पांच गुनी मात्रा हो जाएगी, वह हमें ज्यादा फायदा करेगी। गौशाला में सौर ऊर्जा से बिजली भी बनाएंगे।

पशुपालन महाविद्यालय के डीन डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कृषि के साथ पशुपालन होना चाहिए वह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय मौसम में परिवर्तन बहुत अधिक देखा गया है, रोज की कमाई का साधन पशुपालन हो सकता है, इसमें बकरी पालन है, गोपालन, मुर्गी पालन इस तरह की अनेक योजनाएं है, जिसमें सरकार के द्वारा बहुत अधिक सहयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही बहुत उत्सुकता के साथ किसानों को पशुपालकों को अनेक लाभ के लिए योजनाएं दे रही हैं, गत दिनों ही प्रधानमंत्री ने दुग्ध उत्पादन के लिए 3 हजार करोड़ की योजनाएं शुरू की है, जिनसे केवल दुग्ध उत्पादन की जितनी भी योजनाएं है, उनमें सहयोग किया जायेगा। उन्होंने कहा पशुपालन राज्यमंत्री बहुत उत्साही है, ऊर्जावान है, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है कि जो रोड पर पशु हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई हुई है। सभी पशुपालकों को इसमें सहयोग करना होगा।

उपसंचालक पशुचिकित्सा डॉ संजय पाण्डे ने कहा पशुपालन एवं डेयरी विभाग 14 जनवरी से 13 मार्च तक पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवधि में दमोह जिले में संगोष्ठी, विकासखंडों में शिविरों का आयोजन, स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिताएं और गौशालाओं में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आज हम जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया है, इस शिविर में पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय के अधिष्ठाता और उनके साथ आए हुए प्रोफेसर की टीम के द्वारा सुबह से ही बहुत सारे पशुओं का उपचार किया गया।

उन्होंने कहा पशुपालन मंत्री लखन पटेल के प्रयासों से लगातार हमारे विभाग को नई नई तकनीक मिल रही है। पशुपालन विभाग की योजनाओं से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन से जिले में जो गाय तैयार की है, उसका प्रदर्शन किया है, अभी तक जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमेन से लगभग 4 हजार से अधिक मादा वत्स तैयार किए हैं, लगभग 1000 से ज्यादा गाय तैयार हो गई हैं, जिन्होंने दूध देना प्रारंभ कर दिया है। पशुपालन विभाग के समस्त कर्मचारी इसमें तेजी के काम कर रहे है। अभी हमारा 06 हजार का लक्ष्य था, इस बार 08 हजार से लेकर 10 हजार का लक्ष्य लेना है। इसको पूरा करके बहुत सी समस्याएं दूर होगी।

अनूपपुर जिले में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां: कानून व्यवस्था पर सवाल

सुशील सोनी । सिटी चीफ
अनूपपुर, अनूपपुर जिले में किसकी है यह बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां स्थित 9 ; 10 कोयला खदान में जो की ऐ सी सी एल द्वारा संचालित है मैं बिना नंबर की गाड़ियां लगाई जाती हैं आरटीओ या कोई भी विभाग इनमें हस्तक्षेप नहीं करता है यह ओवरलोड गाड़ियों से बगल में चलने वाले रहेगिर गाड़ी में से कोयला गिरने में चोटिल हो जाते हैं लेकिन उन राहगीर की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी क्योंकि गाड़ी में तो नंबर ही नहीं है पुलिस खाना पूर्ति करते हुए जब शिकायत होती है तो छोटा-मोटा चालान करके छोड़ देते हैं अभी हाल में ही भालूमाड़ थाने में एक ओवरलोड हाईवे पकड़ा गया जिसमें मात्र से ज्यादा कोयला भर गया था एवं उसे हाईवे में नंबर

प्लेट भी नहीं थी शासन को ओवरलोड कोयला कैसे निकाला यह जांच का विषय है उसमें कोई जांच नहीं की गई गाड़ी का चलन करके छोड़ दिया गया किसकी शह पर कोयल का ओवरलोड होकर जाना शासन को प्रबंधन द्वारा यह भी नहीं बताया जाता की कुल कितनी गाड़ी चल रही हैं और कभी आरटीओ महोदय भी आकर चेक नहीं करते हैं की किस गाड़ी में नंबर है या नहीं है छोटी गाड़ियां तो आरटीओ एवं ट्रैफिक हैं लेकिन यह बड़े-बड़े हाईवे बिना नंबर के चल रहे हैं उन पर सिर्फ दिखावे की कार्यवाही की जाती है कोल माइंस से निकलने वाला कोयला से मिलने वाले राजस्व की चोरी भी एवं कोल माइंस के अधिकारियों की मिली भगत से यह कोयला कहां जा रहा है उसके कागजात भी गाड़ियों में नहीं रहते हैं यदि कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कैसे पता लगेगा कि किस नंबर गाड़ी से घटना हुई है। अनूपपुर जिले में स्थित सभी कोयला खदानों का यही हाल है बिना नंबर की गाड़ी ओवरलोडिंग से होने वाली घटना दुर्घटना आम बात है शासन कब इन गाड़ियों में नंबर डलवाएगा यह तो सोचने की बात है कब उनकी जांच होगी क्या ऐसा नियम नहीं आ सकता है कि बिना नंबर की गाड़ियों में कोयला लोड ही नहीं किया जाएगा।

अवैध रेत उत्खनन माफिया के विरूद्ध कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा रेत चोरी करके ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली को रंगे हाथों पकड़कर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिहं, आरक्षक राजेश बड़ोले, सत्यवीर तोमर के द्वारा ग्राम परसवार में टाटा कंपनी की डग्गी (टिप्पर) क्रमांक MP18G4537 चेचिस न म ब र MAT454203 ॥7P18487 एवं इंजन नम्बर 497TC41PSY838786 के चालक के द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था जो मौके पर चालक अंकित पासी पिता मनोहर पासी

उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम परसवार से डग्गी मय लोड रेता के जप्त कर थाना कोतवाली अनूपपुर में डग्गी चालक अंकित पासी एवं वाहन स्वामी राकेश विश्वकर्मा निवासी वार्ड न. 09 अनूपपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 128/25 धारा 303(2), 317(5) बी.एन.एस.4/21 खान खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की जा रही है। थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन कर रेत चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है।

ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर नव विवाहिता ने जहर खाकर दी जान

बेटी के विवाह के लिए मृतका के पिता से ससुर ने की थी 4 लाख की डिमांड

छत्रसाल सिंह । सिटी चीफ सतना, जिले के कोठी कस्बे में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ससुराल की प्रताड़ना से परेशान होकर 27 वर्षीय नेहा पांडेय ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेहा के ससुर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए नेहा के पिता से 4 लाख रुपये की मांग की थी जिसमें मायके पक्ष ने 50000 नगद दिया था बाकी रुपये न दे पाने की स्थिति में नेहा को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। और घर में सास % मौसी सास% ससुर और पति ने पहले मारपीट की फिर जहर खिला कर आत्महत्या बताया जानकारी के मुताबिक, नेहा की शादी 4 साल पहले हुई थी।आत्महत्या से पहले उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी। मायके वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष की लगातार यातनाओं ने उसे इस कदम तक पहुंचा दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शराब की अवैध बिक्री पर लगाई जाए रोक

छत्रसाल सिंह । सिटी चीफ
सतना. अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद ने कोठी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है।शुक्रवार को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में इन दिनों शराब की बिक्री की जा रही है।जिसके चलते युवा वर्ग नसे की चपेट में तो आ ही रहा है साथ ही गांवों में आए दिन लड़ाई झगड़े भी शराब खोरी की वजह से हो रहे है।

खुले आम पीते है शराब
सौंपे गए ज्ञापन में यह भी बताया गया कि बहुतायत मात्रा में शराब की पैकरी गांव गांव होने के चलत लोगो को बाद सहजता से शराब उपलब्ध हो रही है।इसके चलते इसका सेवन वह खुले आम करते।सार्वजनिक जगहों खड़े होकर शराब पी रहे होते है।तो उसी समय गांव में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी निकल रहे होते है।जिस वजह से सभी पर गलत असर पड़ रहा है।

बाग नगरवासियों ने खूब खेली होली

हर्षोल्लास से मनी शीतला सप्तमी पर होली

बाग-नगर में शितला सप्तमी का पावन पर्व हर्सोल्लास एवं आस्था के साथ मनाया गया। इस दिन परंपरा अनुसार नगर में होली सुबह आठ बजे बाद से ही बच्चों की टोलिया अबीर-गुलाल लेकर रंग खेलने निकल पड़। जैसे जैसे दिन चढता गया उसी प्रकार रंग खेलने का सिलसिला बढ़ता गया। 11 बजे होली का रंग हर गली मोहल्ले हर चौराहे पर चढ़ने लगा,युवाओं की टोली एक दूसरों को रंग लगाते हुए व होली की बधाई देते हुए अपनी मस्ती में मस्त फाग के गीत गाते हुए नजर आए। वही माता दरवाजा मे समाज पटेल के निवास प्रांगण में गुजराती राजपूत समाज जनों ने डीजे पर महिलाओं व युवतियो ने गरबा नृत्य के युवाओ ने अपनी मस्ती में मस्त होकर नाचते रहे। पूरा नगर ही रंगों में रंगारंग नजर आया सिर्वी मोहल्ला आइजी मंदिर प्रांगण में महिलाओं द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गरबा नृत्य किया, साईसिटी कालोनी मे बच्चों ने भी पानी व रंग से पूरे दिन मस्ती कर आनंद लिया, वही नगर के मध्य गंधी पुल पर संचीन सोनी मित्र मंडल द्वारा ढोल की थाप पर व डीजे की धुन पर दिन भर थिरकते हुए नजर आए, वही दुपहर में बंशी कॉलोनी से मुख्य मार्ग होते हुए विजय स्तंभ चौराहे तक युवा समाजसेवी संदिप मण्डलोई के नेतृत्व में सैकड़ो युवाओं की टोली एवं महिलाओं द्वारा गैर निकालकर डीजे की धुन पर जमकर रंग गुलाल उड़ाया व हर्बल रंग से होली खेलने का संदेश दिया।, उत्साह व उमंग से होली मनाई, व सूखे रंगों के दिनभर गुबार उड़ते रहे।पवित्र रमजान माह जुम्मे हुए नमाज, प्रशासन रहा अलर्ट बाग मे शीतला सातम पर होली खेलने वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है। ऊपर वाले का सजोक देखो राजा मोरधज की विराट नगरी मे होली के रंग मस्ती और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज मैं इबादत दोनों एक साथ सम्पन्न हुई। । इस वर्ष शीतला सप्तमी ओर जुम्मा एक साथ होने सें पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सब कुछ शांति, उत्साह, उमंग व भाईचारे से पूर्ण हुआ। होली भी जुम्मे की नमाज भी। खूब रंग उड़े। खूब इबादत भी हुई। रंग से सराबोर चेहरे भी दिखे तो झक सफेद कुर्त-पायजामे में नमाजी भी सड़कों पर थे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा स्वच्छता रील प्रतियोगिता का आयोजन

15 अप्रैल तक पांच सबसे अधिक वायरल रील बनाने वाले प्रथम विजेता को 2 लाख रुपये का पुरस्कार

खरगोन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा 'स्वच्छ एमपी रील्स प्रतियोगिता' का आयोजन किया जा रहा है। रील वीडियो लिंक शेयर करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 तक है। राज्य स्तरीय रील्स प्रतियोगिता की थीम 'कचरा नहीं, यह कंचन है इसे अलग-अलग करें और पैसा कमाएं पर केन्द्रित विषय-मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्राम का उचित अपशिष्ट प्रबंधन पर रील्स बनाना है, जिनके मुख्य 3 विषय है- गीला-सूखा कचरा अलग-अलग रखना एवं उचित निपटान, कचरे का दोबारा उपयोग तथा खुले में कचरा नहीं फेंकना विषय पर बना सकते हैं। इसमें से किसी भी एक विषय पर रोचक रील तैयार करें। अपनी रील को सोशल मीडिया प्लेटफार्म (एक्स, यूट्यूब, फेसबुक) पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रील को द्धह्लह्लश्चह्य-//द्बश्च.द्ब4द्द्श1.द्बठ्ठ पर सबमिट करके प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। पांच सबसे अधिक वायरल रील बनाने वाले प्रथम विजेता को 2 लाख रुपये, द्वितीय को एक लाख रुपये, तृतीय को 50 हजार रुपये तथा 02 सांत्वना पुरस्कार 25-25 हजार रुपये के प्रदान किये जायेंगें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये वेवसाईट https://mp.mygov.in लिंक पर विजिट कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं, रचना कर्मियों और विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन से संबंधित विचारों और समाधानों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी सुरक्षित अपशिष्टि निपटान से संबंधित वीडियों बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते है।

वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक चुनाव पर मंथन होना चाहिए निलेश भारती

धार
वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर भाजपा की विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी से परिचर्चा का आयोजन हुआ
एक देश-एक चुनाव पर मंथन होना चाहिए- निलेश भारती

धार। भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर नगर के विभिन्न एसोसिएशन एवं सामाजिक संगठन के प्रमुख पदाधिकारी से भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती के साथ सुझाव व परिचर्चा का आयोजन हुआ । परिचर्चा में जिला टोली सदस्य अभिभाषक देवेंद्र सोनाने आशुतोष विजयवर्गीय और भाजपा जिला मंत्री जीवन रघुवंशी मौजूद रहे।

भाजपा जिला अध्यक्ष निलेश भारती ने कहा कि देश की आर्थिक शक्ति को विश्व में तीसरे पायदान लेन के लिए एक देश-एक चुनाव पर मंथन होना चाहिए एक देश एक चुनाव हमारे संविधान के मूल संरचना के रूप है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी स्टेप है जो संविधान की प्रस्तावना में पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए मुहिम चालू करने का निर्णय लिया गया है। प्रशासनिक अमला जो साल भर चुनाव में लगा रहता है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। चुनी सरकार पांच साल काम करेगी। जनता चुनेगी कि पांच साल बाद किसको लाना है कौन सरकार चुनकर आएगी। यह समाज के सभी वर्गों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 2034 तक वन नेशन-वन इलेक्शन का क्रियान्वयन शुरू होगा। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है यह नेशनल एजेंडा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को हम जन आंदोलन बनाएंगे। आने वाले दिनों में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी एवं परामर्श सम्मलेन तथा विचार गोष्ठी का आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विशाल निगम और जयराज देवड़ा नगर पेंशनर एसोसिएशन, भोज उत्सव समिति अभिभाषक संघ मंडी व्यापारी संघ विद्यार्थी परिषद जन भागीदारी समिति गौ सेवा समिति इंजीनियर एसोसिएशन, सेमी

होलसेल व्यापारी संघ माली समाज मराठा समाज समेत विभिन्न संगठनो के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कसरावद में पुलिसकर्मियों को मिला तनाव मुक्त जीवन का मंत्र

कार्यक्रम मे हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र के सदस्य, पुलिस परिवार एवं स्टाफ़ शामिल हुए

खरगोन पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में पुलिसकर्मियों को तनावमुक्त करने व उन्हें स्वास्थ रखने हेतु योग शिविर का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया था ।इसी क्रम में थाना पर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बर्मन के द्वारा थाना परिसर में पुलिसकर्मियों व उनके परिवार वालो के लिए योग शिविर आयोजित किया गया जिसमें योग करने से होने वाले फायदे जैसे तनाव से मुक्ति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ, सुदृढता व जीवन मे सकारात्मकता लाने के लिए ध्यान व योग को दिन प्रतिदिन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया । साथ ही निकट भविष्य मे भी इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बताया गया। साथ ही हार्टफुलनेस ध्यान केंद्र के सदस्यो का भी आभार व्यक्त किया ।

जल संरक्षण हेतु दिलवाई गई शपथ

झाबुआ ....राज्य कार्यालय के निर्देश और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद झाबुआ जिला समन्वयक भीमसिंग डामोर एंव थांदला विकास खंड समन्वयक वर्षा डोडियार के मार्गदर्शन मे विश्व जल दिवस के अवसर पर ब्लॉक थांदला जिला झाबुआ की नवांकुर संस्था महावीर समग्र ग्राम विकास समिति ग्राम रनी तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कसाडिया , कुकडिपाड़ा , द्वारा जल के महत्व को बताते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।और जल स्त्रोतों की साफ सफाई कर जल संरक्षण हेतु शपथ भी दिलाई गई जिसमें संस्था से कमजी कटारा , हवसिंग कटारा , शांतिलाल मेडा , रमेश सिंगाड एंव अन्य ग्रामीणों जनों ने सहभागिता की ।

विश्व जल दिवस के अवसर पर श्रमदान कर किया गया वृक्षारोपण

झाबुआ

झाबुआ- विश्व जल दिवस के अवसर पर आज जल स्रोत के आसपास श्रमदान कर वृक्षारोपण किया गया। राज्य शासन के निर्देश अनुसार आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला समन्वयक भीम सिंह डामोर के निर्देशन में झाबुआ जिले के विभिन्न ब्लाकों में जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

जिसमें ब्लॉक झाबुआ सेक्टर कल्याणपुरा की नवांकुर संस्था संस्कृति युवा मंडल समिति भगोर द्वारा ग्राम के जल स्रोत के आसपास साफ सफाई की गई पश्चात विद्यालय परिसर में बच्चों के माध्यम से वृक्षारोपण किया गया । इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष अर्चना बैरागी ने बच्चों को बताया कि एक समय में हमारी नदियां कलकल बहती थी आज उनमें पानी की भारी कमी है। हमारे विभिन्न जलस्तर जैसे हैंडपंप, कुएं ,बावड़ी तालाब आदि मार्च माह में ही सुख जाते हैं। हमारी भूमि का जलस्तर गिरता जा रहा है ऐसे में जल स्रोतों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण में वृक्षारोपण की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाए। इस कार्यक्रम में राहुल नायक, राजेश बैरागी , मनसा बैरागी गौतम डोडिया , विनीत झनिया, आदि ने सहभागिता की ।

कविता दिवस पर कविसम्मैलन तथा कवि का सम्मान किया

उज्जैन

कविता दिवस के उपलक्ष मे नगर के साहित्य और संस्कृती प्रेमी ग्रूप द्वारा नगर की पौरवाल धर्मशाला मे नगर कवि जिन्हौने इस नगर का नाम काव्य के क्षेत्र मे पूरे देश मे रौशन किया ऐसे कवि श्रीनारायण निडर का सम्मान तथा कवि सम्मैलन का आयौजन कीया । इस अवसर पर निडर जी कौ नगर के साहीत्य प्रेमियौ द्वारा 51000/ की राशी तथा इस ग्रूप केसंरक्षक तथा वरिष्ट समाजसेवी भा.ज.पा नैता श्री

सुर्यप्रकाश जी शर्मा ने 21000/ की राशी तथा शाल श्रीफलसे सम्मानित किया । ग्रूप के संजय मेहता ने बताया की नगर के साहीत्य प्रेमियौ की यह इच्छा थी की नगर के ऐसे कवि जिन्हौने कविता के माध्यम से इस नगर का नाम पूरे भारत मे रौशन किया उनका सार्वजनिक अभिनन्दन्न करके सम्मानित कीया जाये उसी कडी मे यह कार्यक्रम आयौजित किया गया । इस अवसर पर श्री निडर के सम्मान मे बाहर से पधारे हुये कवि श्री सुरेन्दं सर्किट, धमचक मूलथानी, दिपिका पाटिदार, डा. औम बेरागी, तथा रईस भाई द्वारा काव्य पाठ किया गया । इस अवसर पर नगर के विभीन्न सुन्दर कांड मंडलौ तथा सामाजिक संस्थाऔ के प्रमूख लौगो का सम्मान भी किया गया । ग्रूप के डा. राधेश्याम जी वरवानीया ने सहयोग करने वाले सभी महानुभावो का आभार किया । इस अवसर पर बडी संख्या मे नगर के साहित्य प्रेमी उपस्थित थे । आभार संजय मेहता ने माना ।

विश्व जल दिवस के अवसर पर संगोष्ठी कर किया गया श्रमदान

झाबुआ पेटलावद- विकासखंड मेघनगर मे विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण हेतु ग्राम तलावली मैं भीम सिंह पाल के द्वारा ग्राम में संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम वासियों ने जल संरक्षण एवं जल के महत्व को समझा । आदर्श ग्राम छोटा गुडा में वीर सिंह थडार के द्वारा जल संरक्षण हेतु समुदाय बैठक लेते हुए हैंडपंप के आसपास साफ सफाई करते हुए श्रमदान का कार्य किया । ग्राम नौगांवा में दीपिका मंडलोई के द्वारा आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ

किशोरी बच्चियों को जल का महत्व समझाया ओर जागरूकता बैठक ली गई । ग्राम शिवगढ़ में शिवगढ़ की गड़ी की बावड़ी की साफ सफाई का कार्य मनीष परमार परामर्शदाता के द्वारा एमसीएमसीएल् डीपी छात्रों के साथ संपन्न किया गया एवं उन्हें जल के महत्व को समझाते हुए जल के स्तर को बढ़ाने के लिए पौधा रोपण करने के लिए प्रेरित किया गया । वहीं पेटलावद विकासखंड में भी ब्लॉक समन्वयक प्रवीण पवार के निर्देशन में मेंटर विनोद बाफना ने सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को जल का महत्व बताते हुए नहीं जल संरक्षण हेतु शपथ दिलवाई ।वही ग्राम कारवड़ में भी जल संरक्षण हेतु कार्यक्रम किए गए । सेक्टर रायपुरिया के रतांबा ग्राम में सेक्टर प्रभारी अन सिंह अरड द्वारा संगोष्ठी कर ग्राम वासियों को जल संरक्षण की ।शपथ दिलाई गई और जल स्त्रोतों के आसपास साफ सफाई भी करवाई गई।

विश्व जल दिवस पर काल भैरव मंदिर में नटनागरा तालाब का पूजन किया

धार

धार । मध्य प्रदेश जनअभियान परिषद द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर स्थानीय काल भैरव मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जिसमे नटनागरा तालाब में पुष्पांजलि अर्पित कर पूजन अर्चन किया । वही छात्रों को जिला स्तरीय नवाअकुंर नवनीत जैन ने संबोधित करते हुए जल ही जीवन है के संकल्प का भी बोध करवाया एव जल का किस प्रकार से सरक्षण व बचाव किया जा सकता है इस पर भी प्रकाश डाला । कार्यक्रम मे मुख्य रूप से काल भैरव मठ के महंत मनोज योगी,

भरतनाथ योगी, मेंटर महेंद्र सिंह ठाकुर एवं विधार्थी संयुक्ता कटारे, हर्ष नागर, धर्मेंद्र चौहान, जयेश सक्सेना एव अनेक युवा साथी उपस्थित थे.

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस विरोध किया ...पुलिस ने किया गिरफ्तार

उज्जैन

उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के विरोध में उज्जैन से लगाकर जावरा तक के गांव के हज़ारों किसान धरना प्रदर्शन व पैदल यात्रा करने को लेकर जोयो होटल जावरा पर एखट्टे हुए थे लेकिन भारी पुलिस बल ने 40 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया और बाकी किसानों को तीतर वीतर कर दिया ! वहीं किसानों को रोड को लेकर इसलिए नाराजगी है

किसन चाहते हैं कि यह फोर लाइन नॉर्मल हाईवे बने ना कि इतना ऊंचा बने और दूसरी बात भूमि अधिग्रहण की राशि चार गुनामुआवजा दिया जाए ! वहीं किसानों का यह कहना है कि यह रोड किसानों के लिए अभी श्राप है जिन किसानों की गांव ग्रामीणों की जमीन जा रही है अगर उन्हें चढ़ने उतरने के उपयोग में नहीं आता है तो फिर किस काम का अगर इंदौर सिक्स लेन रोड 27 मीटर जगह में बनाया जाता है तो फिर इस फोरलेन के लिए 60 मीटर जगह क्यों अधिग्रहण की जा रही है इतना ऊंचा क्यों बनाया जा रहा है जोकि ग्रामीण व आस पास के लोगों को ना रोजगार मिलने का और ना ही कोई सुख सुविधा मिलेगी ! रोड अगर बनाना ही है तो जैसा कि उज्जैन बड़नगर फोर लाइन बना है उज्जैन आगर फोर लाइन बना है ऐसा बनाया जाए !

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

लगा 50 हजार का जुर्माना, तंत्र क्रिया की आड़ में महिला से किया था रेप

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की एक अदालत ने तंत्र क्रिया की आड़ में एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में तांत्रिक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर को इस मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नरेंद्र सिंह

ने जेल में जो समय काटा है उसे भी सजा में समायोजित किया जाए और यह भी कहा कि जुर्माना ना जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के संदर्भ में बरसाना के थाना प्रभारी अरविंद कुमार निर्वाल ने बताया कि दुष्कर्म की यह घटना 4 जून 2021 की है, जब थाना क्षेत्र के ही एक गांव की पीड़ित महिला के पति ने शिकायत दी थी कि राजस्थान के थाना बयाना के नगला बंडा निवासी तांत्रिक नरेंद्र गुर्जर ने उनकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसे तांत्रिक विद्या से ठीक करने का जिम्मा लिया था।

महिला से दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

शिकायत में आरोप लगाया कि इसके बाद इलाज के बहाने तांत्रिक ने उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर 19 जुलाई 2021 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद सजा सुनाए जाने तक कुल 4 साल आरोपी जिला कारागार में बंद रहा है।

मथुरा में होली के दौरान बवाल

गांव में दलितों को जबरन लगाया रंग... 42 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के एक गांव में होली के दिन दलितों के एक समूह पर जबरन रंग लगाने के आरोप में करीब 42 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार जैत थाना क्षेत्र के बाटी गांव में धुलेंडी (रंगोत्सव) के दिन उस समय झड़प हो गई जब ऊंची जाति के कुछ युवकों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर कथित तौर पर जबरन रंग लगाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला किया तथा पथराव भी किया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने 32 दलितों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनमें से 9 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को दलित समूहों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और मांग की कि दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) संदीप कुमार ने बताया कि बाटी गांव की एक महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत 42 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने बताया कि मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस की जांच जारी है।

अमेरिकाः न्यू मैक्सिको के पार्क में हुई फायरिंग, 3 की मौत, 14 जख्मी

इंटरनेशनल डेस्क . अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के लास क्रूसेस शहर में एक पार्क में हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए।

कहां और कब हुई घटना?

पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी शुक्रवार रात करीब 10 बजे यंग पार्क में हुई। यह पार्क संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

घायलों का इलाज जारी

घायलों को लास क्रूसेस के तीन स्थानीय अस्पतालों और यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ एल पासो में भर्ती कराया गया है।

मेमोरियल मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता एंड्रयू कमिंस ने बताया कि छह घायलों को लाया गया था, जिनमें से पांच को एल पासो रेफर किया गया है।

पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश

लास क्रूसेस पुलिस के साथ न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस, डोना एना काउंटी शेरिफ ऑफिस, एफबीआई और एटीएफ एजेंसी इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस ने आसपास के इलाके को बंद कर दिया है और लोगों से घटना से जुड़े वीडियो या सुराग साझा करने की अपील की है।

मेयर ने जताया दुख

लास क्रूसेस की सिटी काउंसलर और मेयर प्रोटेम जोहाना बेंकोमो ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए लिखा, ऐसी घटनाएं हमारे शहर में होंगी, यह कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब यह डरावना सच बन चुका है।

इलाके में सुरक्षा कड़ी

पुलिस ने यंग पार्क और उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया है। लास क्रूसेस शहर अमेरिका-मैक्सिको सीमा से करीब 66 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश जारी है।

पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार, इस तारीख को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी

रोमः कैथोलिक ईसाई धर्म के शीर्ष नेता पोप फ्रांसिस को रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पोप (88) दोनों फेफड़ों में निमोनिया के गंभीर संक्रमण की वजह से पिछले 38 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं।

जेमेली अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. सर्जियो अल्फिएरी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को वेटिकन में कम से कम दो महीने पूरी तरह से आराम करने की जरूरत होगी। पोप फ्रांसिस को ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ने के बाद 14 फरवरी को जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें निमोनिया का गंभीर संक्रमण हो गया।

एक अन्य घटनाक्रम में, वेटिकन ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस रविवार की सुबह अस्पताल की 10वीं मंजिल स्थित अपने कमरे की खिड़की से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे। फ्रांसिस ने छह मार्च को एक ऑडियो संदेश जारी किया था और वेटिकन ने 16 मार्च को उनकी एक तस्वीर साझा की थी। 14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद पोप पहली बार आशीर्वाद कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के सामने आएंगे।

18 घंटे बाद लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहला विमान उतरा

पावर कट के कारण हजारों यात्री प्रभावित

इंटरनेशनल डेस्कः लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के पास एक विद्युत उपकेंद्र में आग लगने और हवाई अड्डे को बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद वहां विमानों का परिचालन करीब 18 घंटे तक ठप रहा और भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात ही पहला विमान हवाई अड्डे पर उतर सका। ब्रिटिश एयरवेज का विमान सूर्यास्त से ठीक पहले यहां उतरा। हीथ्रो विमान सेवा द्वारा परिचालन पर लगी रोक हटाने के बाद विमान का परिचालन शुरू हुआ।

हवाई अड्डे पर बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक पर अफरातफरी की स्थिति रही और हजारों यात्री प्रभावित हुए। उड़ान सेवा पर नजर रखने वाली 'फ्लाइटरडार 24% ने कहा कि हीथ्रो से आने-जाने वाली कम से कम 1,350 उड़ानें प्रभावित हुईं और इस घटना का असर कई दिनों तक रहने की आशंका है, क्योंकि यात्री अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से तय करने का प्रयास करेंगे।

अधिकारी अब तक आग लगने के कारण का पता नहीं लगा सके हैं, लेकिन अभी तक आग के पीछे किसी गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले हैं। पश्चिमी लंदन के निवासियों ने बताया कि जब हवाई अड्डे के पास विद्युत उपकेंद्र में आग लगी, तो उन्होंने एक बड़ा धमाका सुना, जिसके बाद आग का गोला और धुएं का गुब्बार उठता दिखा। 'फ्लाइटरडार 24% के अनुसार, जब हवाई अड्डे को बंद करने की घोषणा की गई, तब लगभग 120 उड़ानें आसमान में थीं, जिनमें से कुछ को वापस भेज दिया गया और अन्य को लंदन के बाहर गैटविक हवाई अड्डे, पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे या आयरलैंड के शैनन हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया।

लॉरेंस हेस नामक यात्री ने बताया कि न्यूयॉर्क से लंदन के लिये तीन-चौथाई सफर को तय करने के बाद वर्जिन अटलांटिक ने घोषणा की कि उड़ान को ग्लासगो की ओर मोड़ा जा रहा है। हीथ्रो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है।

इस साल की शुरुआत में जनवरी में यह सबसे व्यस्त रहा था, जब 63 लाख से अधिक यात्री इस अवधि में यहां से यात्रा कर चुके हैं, जो पिछले साल की इसी अवधि से पांच प्रतिशत अधिक है। हालांकि, शुक्रवार को शटडाउन की स्थिति 2010 में आइसलैंड के एज्जाफ्याल्लाजोकुल ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उत्पन्न स्थिति से कम गंभीर है। उस समय वायुमंडल में राख के बादल फैल गए थे और महीनों तक अटलांटिक पार की हवाई यात्रा प्रभावित रही थी। ऊर्जा मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है।

उन्होंने कहा, '' हवाई अड्डे से लगभग दो मील (3 किलोमीटर) दूर लगी इस भीषण आग के कारण का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें किसी गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं है। लंदन महानगर पुलिस बल ने कहा कि आतंकवाद-रोधी जांचकर्ता जांच का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वे आग के कारण का शीघ्र पता लगाने में सक्षम हैं, तथा विद्युत उपकेंद्र में आग का स्थान तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचना पर इसके प्रभाव को भी अच्छी तरह समझते हैं।

मिलिबैंड ने कहा कि आग पर काबू पाने में सात घंटे लगे, जिससे हवाई अड्डे की आपात बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। हीथ्रो ने एक बयान में कहा कि उसके पास हवाई अड्डे को दिन भर के लिए बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंदन दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए 10 अग्निशमन वाहन और लगभग 70 अग्निशमन कर्मी भेजे तथा लगभग 150 लोगों को विद्युत केंद्र के नजदीक स्थित उनके घरों से निकाला गया।

हवाई अड्डा प्रशासन ने बताया, ''हमें आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण व्यवधान की आशंका है, और यात्रियों को हवाई अड्डे के पुनः खुलने तक किसी भी परिस्थिति में हवाई अड्डे की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आग लगने की वजह से हवाई यातायात पर हुए व्यापक प्रभाव के कारण ब्रिटेन की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि एक आग से अगर यूरोप का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बंद हो सकता है, तो यह संकेत करता है कि देश आपदा या किसी प्रकार के हमले के लिए तैयार नहीं था। सुरक्षा थिंक टैंक हेनरी जैक्सन सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक एलन मेंडोजा ने कहा, ''ब्रिटेन का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा उस स्तर तक पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिस स्तर पर इसे होना चाहिए। यह हमें विश्वास नहीं दिलाता कि ऐसा दोबारा नहीं होगा।

उन्होंने कहा, ''यदि एक आग हीथ्रो की प्राथमिक प्रणालियों को बंद कर सकती है और फिर जाहिर तौर पर आपात प्रणालियों को भी, तो इससे पता चलता है कि ऐसी आपदाओं के प्रबंधन की हमारी प्रणाली में कुछ गड़बड़ है। प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के प्रवक्ता टॉम वेल्स ने माना कि अधिकारियों के पास जवाब देने के लिए प्रश्न हैं और कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर जांच की आवश्यकता है कि ''इस पैमाने पर व्यवधान फिर से न हो। लंदन के अग्निशमन विभाग ने विद्युत उपकेंद्र में लगी आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल वाहन और करीब 70 अग्निशमन कर्मी भेजे और करीब 150 लोगों को विद्युत उपकेंद्र के नजदीक बने घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग लगने से 67,000 ग्राहकों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, हालांकि सुबह होने तक अधिकांश आपूर्ति बहाल कर दी गई।

युवराज सिंह ने क्रिकेट में की वापसी, भारत-पाकिस्तान मैच में खेलते आएंगे नजर

नेशलन डेस्क. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, जो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी चमक छोड़ चुके हैं, इस बार एक नई चुनौती के साथ मैदान में वापसी करने जा रहे हैं। वह जुलाई में यूनाइटेड किंगडम में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (ङ्खष्टरु) के दूसरे संस्करण में भारत की टीम का नेतृत्व करेंगे। युवराज सिंह का यह कदम भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि वह पिछले संस्करण में भारतीय टीम को खिताब दिला चुके थे। इस बार भी उनकी कप्तानी में टीम इंडिया चैंपियंस के जीतने की संभावना को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जोश है।

पिछली जीत की यादें

युवराज सिंह के लिए पहला ङ्खष्टरु संस्करण एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने न केवल टीम का शानदार नेतृत्व किया, बल्कि भारत को खिताब दिलाकर क्रिकेट जगत में एक नई मिसाल कायम की। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था, और इस जीत ने उन्हें और उनकी टीम को क्रिकेट प्रेमियों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। युवराज ने कहा, पहले संस्करण की जीत और अपने साथियों के साथ बिताए गए शानदार पल हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे।

दूसरे संस्करण में युवराज सिंह के साथ अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भी भारत की टीम का हिस्सा होंगे। शिखर धवन जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, अब WCL 2025 में डेब्यू करने जा रहे हैं। युवराज और शिखर का साथ मिलकर भारत की टीम को और भी मजबूत बना सकता है। इस बार, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण

अफ्रीका जैसे दिग्गज टीमों से मुकाबला करना होगा, और ये मुकाबले क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव साबित हो सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला

WCL 2025 का सबसे रोमांचक पल वह होगा जब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट में एक बड़ी प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा रहा है, और इस बार यह मैच और भी अधिक दिलचस्प होगा। दोनों देशों के बीच की यह जंग हमेशा से प्रशंसकों को उत्साहित करती है, और इस बार भी इसका मुकाबला देखने के लिए हर क्रिकेट प्रेमी बेचैन रहेगा।

सह-मालिक सुमंत बहल का उत्साह

इंडिया चैंपियंस टीम के सह-मालिक सुमंत बहल ने कहा, पिछले साल पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीतना हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था।

हम इस बार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और खिताब की रक्षा करने के लिए उत्सुक हैं। उनका यह बयान इस बात को दर्शाता है कि टीम पूरी तरह से अपने प्रदर्शन को सुधारने और फिर से ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है।

यह टूर्नामेंट न केवल दिग्गज क्रिकेटरों के लिए एक शानदार मंच है, बल्कि यह प्रशंसकों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर होगा, जहां वे अपने चहेते सितारों को फिर से मैदान में जलवा बिखेरते देख सकेंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (श्वष्टक्च) के समर्थन से आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट ने पहले संस्करण में ही क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी, और इस बार इसका रोमांच और भी बढ़ने वाला है।

युवराज सिंह का उत्साह

युवराज सिंह ने अपनी वापसी को लेकर जो उत्साह दिखाया है, वह उनके और उनके साथियों के लिए सकारात्मक संकेत है।

वह टीम को एक बार फिर से जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके साथियों के साथ टीम की शानदार तैयारियां जारी हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सभी खिलाड़ी बेहद उत्साहित हैं, और हर कोई इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569